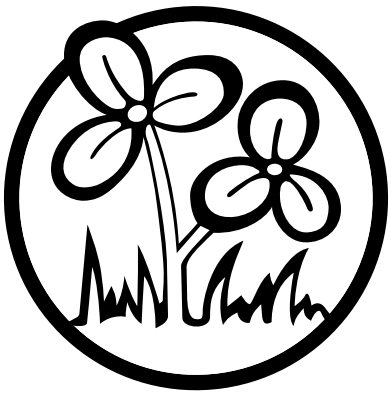
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

घोषणा पत्र 2026





अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

घोषणा पत्र, २०२६

अपील

मेरे प्रिय राज्यवासियों,

बंगाल की मां-माटी-मानुष को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम और आभार अर्पित करती हूँ। पिछले पंद्रह वर्षों में आपने जो विश्वास, स्नेह और समर्थन हमें दिया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिस दिन बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को सेवा का अवसर दिया, उसी दिन से मेरा संकल्प स्पष्ट था—सरकार सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम बनेगी। हमारा विश्वास है कि लोगों का सम्मान, उनका जीवनस्तर और राज्य का विकास—ये सब एक ही सूत्र में जुड़े हुए हैं।

आपके आशीर्वाद से हमने इस विश्वास को निभाया है। आज बंगाल का शासन मॉडल इस बात का प्रमाण है कि जब जनता और उनकी सरकार विश्वास के साथ साथ चलते हैं, तो क्या संभव हो सकता है। पूरे देश में अन्य राज्यों ने बंगाल को एक जीवंत उदाहरण के रूप में देखा है कि जन-केन्द्रित प्रशासन क्या हासिल कर सकता है। इन पंद्रह वर्षों में बंगाल का परिवर्तन पूर्ण रहा है। आज व्यक्ति गरिमा के साथ जी रहा है, परिवार विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित है, हर क्षेत्र आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है, और हमारे राज्य का हर इलाका नई ऊर्जा और अवसरों से स्पंदित हो रहा है।

मैं आपको अपना गंभीर वचन देती हूँ कि प्रगति की यह यात्रा रुकेगी नहीं। बंगाल आगे बढ़ता रहेगा।

जैसा कि मैंने हर कार्यकाल में किया है, मैंने आपके सामने हमारे कार्यों का पूरा विवरण "उन्नयोनर पंचाली" — विकास की गाथा — के रूप में रखा है। मुझे गर्व और विनम्रता के साथ यह बताने दें कि हम सबने मिलकर क्या-क्या हासिल किया है।

आज पश्चिम बंगाल भारत की विकास यात्रा के प्रमुख इंजनों में से एक है। हम देश की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है। हमने 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उन्हें वह गरिमा लौटाई है जो हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। बेरोज़गारी में 40% की कमी आई है, साथ ही हमने पूरे राज्य में दो करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्राथमिक स्तर पर कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। हमारी पुरस्कार विजेता कन्याश्री योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक लड़कियों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, जिसे विश्व स्तर पर सराहा गया है। सबूज साथी योजना के माध्यम से 1.44 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल देकर उनके सपनों को पंख दिए गए हैं। ऐक्यश्री, मेधाश्री और शिक्षाश्री छात्रवृत्तियों ने शिक्षा को वास्तव में सार्वभौमिक बना दिया है, ताकि कोई भी बच्चा परिस्थितियों के कारण पीछे न रह जाए।

आज पश्चिम बंगाल में किसी भी परिवार को बीमारी के खर्च से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य साथी योजना के तहत 2.45 करोड़ परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिली है। हमने बंगाल को बिजली कटौती वाले राज्य से बिजली अधिशेष राज्य में बदल दिया है, और 2019 में ही 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया। लगभग एक करोड़ परिवारों को आवास और पाइप से जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है। हमने 1,83,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिससे अंतिम बस्ती तक संपर्क सुनिश्चित हुआ है।

अब "दुआरे सरकार" के माध्यम से शासन आपके दरवाजे तक पहुँचता है। "आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान" और "सोरासोरी मुख्यमंत्री" के माध्यम से आपकी आवाज़ हमारी नीतियों को आकार देती है। 1.10 करोड़ किसानों को कृषक बंधु (नतुन) के तहत सहायता मिली है, और 1.13 करोड़ किसानों ने बांग्ला शस्य बीमा के माध्यम से अपनी फसल को सुरक्षित किया है। फसल तीव्रता और धान उत्पादन में बंगाल देश का नेतृत्व करता है। जूट और चाय के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं। हमारा कोल्ड स्टोरेज ढांचा देश में अद्वितीय है।

और सड़कों और इमारतों से परे, हमने बंगाल की आत्मा का भी पोषण किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। हमने श्रद्धा और समर्पण के साथ दीघा में जगन्नाथ धाम, न्यू टाउन में दुर्गा आंगन और माटीगड़ा में महाकाल मंदिर परिसर का निर्माण किया है। कोलकाता का क्रिसमस विश्वभर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। ईद और मुहर्रम हमारे राज्य में उतनी ही श्रद्धा से मनाए जाते हैं जितने अन्य त्योहार।

बंगाल विविध संस्कृतियों, आस्थाओं और भाषाओं का जीवंत संगम है। हमने इस विविधता के हर सूत्र का सम्मान करने का प्रयास किया है। संथाली, कुरुख, कुर्माली, राजबंशी, कामतापुरी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, ओड़िया, नेपाली और पंजाबी को अब बंगला के साथ आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है — यह इस बात का प्रमाण है कि हर समुदाय महत्वपूर्ण है और हर आवाज़ की गिनती है।

मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि बंगाल आगे भी नेतृत्व करता रहेगा, और अगले पाँच वर्षों में हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रगति से अछूता नहीं रहेगा।

प्रतिदिन मैं उन महान विभूतियों की विरासत से प्रेरित और विनम्र होती हूँ जिन्होंने इस भूमि को आकार दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, काजी नजरुल इस्लाम, ठाकुर पंचानन बर्मा, बाबा साहेब अंबेडकर, श्री श्री हरिचंद ठाकुर, श्री श्री गुरुचंद ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, महात्मा गांधी, सिधु-कान्हू, गुरु नानक, श्री अरविंद घोष, सर प्रफुल्ल चंद्र राय, सर जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, रासबिहारी बोस, मातंगिनी हाजरा, मास्टर दा सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेदार, खुदीराम बोस, और असंख्य अन्य जिन्होंने न्याय, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

मैं इसी क्रांतिकारी भूमि की संतान हूँ। इसकी बेटी के रूप में, मैं अपने जीवन की हर सांस इस भूमि की सेवा, इसके लोगों की सुरक्षा और इसके अमूल्य मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित करती हूँ।

हम एक संघीय लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ केंद्र और राज्य संविधान के तहत पारस्परिक सम्मान और साझा जिम्मेदारी के संबंध में भागीदार होने चाहिए। दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार ने बार-बार इस भावना का उल्लंघन किया है, राष्ट्रीय हित के बजाय बंगाल में सत्ता हासिल करने में असफल रहने की निराशा से प्रेरित होकर।

उन्होंने दिल्ली के जमींदारों की तरह व्यवहार किया है — हमारी भावना से भयभीत, हमारी समृद्धि से ईर्ष्यालु, और जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे कमजोर करने का प्रयास करते हुए। लोकतांत्रिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा करने या बंगाल के लोगों का विश्वास जीतने में असफल रहने के बाद, केंद्र ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत लगभग ₹2 लाख करोड़ की राशि रोक ली है, जिससे गरीबों और वंचितों को उनकी मेहनत की मजदूरी, सिर पर छत, सड़क संपर्क और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया है।

हमने देखा है कि उन्होंने बंगाल के लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया, हमारी भाषा को अपराध घोषित किया, हमारे नागरिकों पर हमला किया, हमारे प्रतीकों का अपमान किया और हमें अपनी ही भूमि में पराया ठहराया। एसआईआर प्रक्रिया इसका एक काला अध्याय है — यह सामान्य मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का सुनियोजित प्रयास था। इसके परिणामस्वरूप 160 से अधिक लोगों की जान गई। आम मतदाता भयभीत था। बुजुर्गों और बीमारों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। वंचितों को सामूहिक रूप से सूची से बाहर कर दिया गया।

वे जानते हैं कि उनके पास आपका जनादेश नहीं है, और इसलिए उन्होंने आपके मतदाता अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए, और यह स्पष्ट किया जाए कि लोकतंत्र कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे मनमाने ढंग से गढ़ा जा सके। यह जनता की इच्छा है — इसे छीना नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, इसे अर्जित करना पड़ता है।

तृणमूल कांग्रेस का एक ही एजेंडा रहा है — बंगाल फर्स्ट। जब विभाजन और भय की ताकतें हमारे राज्य पर उतरीं, तब हमने मातृभूमि के सिपाहियों की तरह डटकर मुकाबला किया। हमने संसद में और सड़कों पर बंगाल के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हमने तब नए सुरक्षा उपाय बनाए जब केंद्र ने पुराने छीन लिए।

पिछले पंद्रह वर्ष "उन्नयन" को बंगाल के सार्वजनिक जीवन के केंद्र में लाने के थे। अगले पाँच वर्ष बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने के होंगे, ताकि दिल्ली का कोई भी जमींदार हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने का सपना भी न देख सके।

आपने मुझे "सोरासोरी मुख्यमंत्री" के माध्यम से पुकारा, और मैंने आपको सुना। जब मैं बंगाल के हर कोने में गई, आप मुझसे मिले और सीधे अपनी बात कही। "आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान" शिविरों में आपने अपने सुझाव दिए, और वे सभी मेरे पास

पहुँचे।

मैंने आपकी एक भी बात को हल्के में नहीं लिया। आपकी हर चिंता, हर मांग, हर सपना — मैंने उन्हें गंभीरता से लिया है।

मैंने आपकी एक भी बात को हल्के में नहीं लिया। आपकी हर चिंता, हर मांग, हर सपना — मैंने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है, उन पर गहराई से विचार किया है, और स्वयं से पूछा है: मैं इस विश्वास का सम्मान कैसे करूँ? जो दृष्टि आगे प्रस्तुत है, वही मेरा उत्तर है।

यह रहे आपके लिए, बंगाल के लोगों के लिए, मेरे दस संकल्प — मेरी दस प्रतिज्ञाएँ। मैं प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत और पूर्ण उत्तरदायित्व लेती हूँ। इन सभी वादों को अगले पाँच वर्षों में वास्तविकता में बदला जाएगा। यह मेरा वचन है।

मैं सुनिश्चित करूँगी कि बंगाल की लक्ष्मियों की थैली कभी खाली न रहे। लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सभी श्रेणियों में ₹500 बढ़ाया जा रहा है।

मैं बंगाल के किसानों के हित में एक समर्पित कृषि बजट प्रस्तुत करने का संकल्प लेती हूँ, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को वह विशेष ध्यान देगा जिसके वे हकदार हैं — किसानों की आय बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और कृषि श्रमिकों को लक्षित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए।

मैं एक युवा के रोजगार की तलाश में होने वाली कठिनाइयों और उसके परिवार पर पड़ने वाली चिंता को समझती हूँ। मैं बंगाल के हर युवा को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। "बांग्लार युवा-साथी" योजना के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को पाँच वर्षों तक प्रति माह ₹1,500 प्रदान किए जाएंगे।

मैं सुनिश्चित करूँगी कि बंगाल का कोई भी परिवार सम्मानजनक आवास से वंचित न रहे। मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि हर घर में कार्यशील पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध हो। मैं चिकित्सा सेवाओं को हर घर तक पहुँचाऊँगी। ब्लॉक स्तर पर वार्षिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर न जाना पड़े।

राज्य के प्रत्येक सरकारी विद्यालय का व्यापक उन्नयन किया जाएगा। मेरा लक्ष्य बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का प्रवेश द्वार बनाना है। इसकी नींव रखी जा चुकी है, और आने वाले वर्षों में हम उद्योग-सज्जित आधारभूत संरचना पर निर्माण करते हुए बंगाल की पूर्ण क्षमता को पूर्वी वाणिज्य के प्राकृतिक गलियारे के रूप में साकार करेंगे।

मैं बंगाल के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को उनके जीवन की संध्या में सुनिश्चित करूँगी, निरंतर वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से।

शासन को जनता के और निकट लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी समुदाय प्रशासन के हाशिये पर न रहे, मैं राज्य के व्यापक भौगोलिक पुनर्गठन के माध्यम से 7 नए जिलों की स्थापना करूँगी और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या का विस्तार करूँगी।

आज मैं जो वादा कर रही हूँ, वह किसी अनजान दिशा में छलांग नहीं है। यह पंद्रह वर्षों के सिद्ध कार्य, परखी गई दृढ़ता और निभाए गए विश्वास पर आधारित है। हमने विशेषज्ञों के एक समूह से परामर्श किया, जिन्होंने आपके अनुभवों को ठोस और क्रियान्वयन योग्य योजनाओं में रूपांतरित किया।

हम दृढ़ रहे हैं, और अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बंगाल भारत और विश्व के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा, यह सिद्ध करते हुए कि कल्याण विकास को गति देता है और विकास, बदले में, कल्याण को गहराई प्रदान करता है।

मैं, ममता बनर्जी, अपने माँ-माटी-मानुष से अपील करती हूँ कि वे जोड़ा-फूल चिन्ह पर बटन दबाकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें। तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। बंगाल के संरक्षकों को वोट दें।

हमें उन लोगों के खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा जिन्होंने हमें बार-बार धोखा दिया है। हमें यह लड़ाई जीतनी होगी ताकि बंगाल की शांति, सद्भाव और मूल आत्मा की रक्षा की जा सके।

आने वाले पाँच वर्षों में, मैं हमारे सामूहिक सपनों को वास्तविकता में बदलने का संकल्प लेती हूँ, इस भूमि की सेवा उसी प्रेम और

समर्पण के साथ करूँगी जो बंगाल हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित करता आया है।

बंगाल के हित में, उस भविष्य को चुनें जो हमारी मातृभूमि का सम्मान करता है। उन संरक्षकों को चुनें जिन्होंने हर कठिनाई में इस राज्य का साथ दिया है। चौथी बार तृणमूल कांग्रेस को चुनें।

जय हिंद! जय बांग्ला! जय माँ-माटी-मानुष!

ममता बनर्जी



बंगाल के लिए दीदी की १० प्रतिज्ञा



लक्ष्मी की जय, स्वनिर्भरता अक्षय

लक्ष्मीर भंडार में ₹५०० प्रति माह की वृद्धि - सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ₹१,५०० (₹१८,००० प्रति वर्ष) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ₹१,७०० (₹२०,४०० प्रति वर्ष)

युवाओं के साथ, रोज़गार का भरोसा



आजीविका-हीन युवाओं को 'बांग्लार युबा-साथी' योजना के तहत ₹१,५०० प्रति माह (₹१८,००० प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता

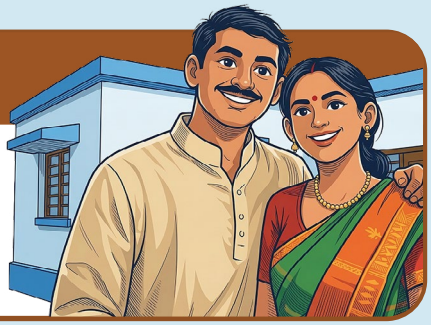


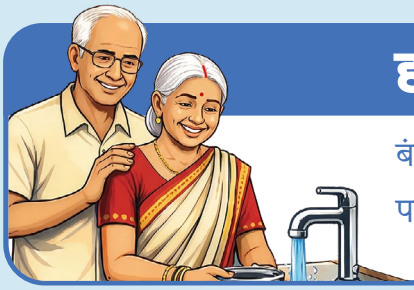
कृषि बजट, किसानों की खुशहाली

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, कृषि परिवारों को निरंतर समर्थन एवं भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹ ३०,००० करोड़ का कृषि बजट

निश्चित आवास, चिंताओं का नाश

बंगाल के हर परिवार के लिए पक्के घर की गारंटी



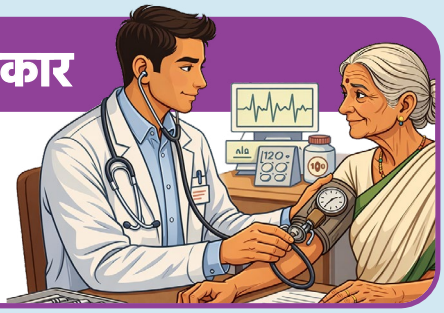


हर घर नल, शुद्ध पीने का जल

बंगाल के हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य

बंगाल में सभी को बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार

प्रति वर्ष प्रत्येक ब्लॉक और शहर में आयोजित 'द्वारे चिकित्सा' कैंप के माध्यम से, प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ अब सीधे आपके द्वार तक





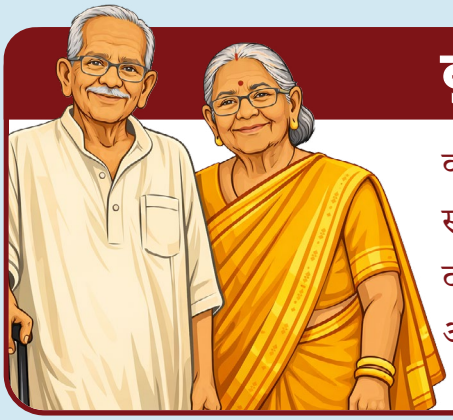
शिक्षा ही संपत्ति, सुरक्षित भविष्य का संकल्प

'बंग्लार शिक्षायातन' के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का पूर्ण विकास

बंगाल बनेगा भारत के पूर्वी व्यापार का सारथी

विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और व्यापारिक बुनियादी ढाँचे के साथ बंगाल बनेगा पूर्वी भारत के व्यापार का प्रवेश द्वार





बुज़ुर्गों के साथ, देखभाल का भरोसा

वर्तमान सभी लाभार्थियों के लिए निरंतर वृद्धावस्था पेंशन सहायता सुनिश्चित की जाएगी और धीरे-धीरे इस सुरक्षा के दायरे का विस्तार कर सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

प्रशासनिक सुगमता से बंगाल नए क्षितिज पर

७ नए ज़िलों का निर्माण; भौगोलिक पुनर्गठन द्वारा नगरपालिकाओं की संख्या में वृद्धि



केंद्र की भाजपा सरकार राज्य के वैध अधिकारों को रोककर बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है।

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आर्थिक एवं विकासात्मक विश्वासघात

» बंगाल पर केंद्र सरकार का लगभग २ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जन कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन रोक रखा है।

१०० दिनों का कार्य
(MGNREGA):
३६,०९५ करोड़ रुपये

ग्रामीण सड़कें
२,७२४.११ करोड़ रुपये

ग्रामीण आवास
१६,१३४.०८ करोड़ रुपये

पेयजल
९९७.९० करोड़ रुपये

» इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, शहरी विकास, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा सिंचाई सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लंबित है।

» उन्होंने खाद्य सब्सिडी के मद में ११,७५०.१९ करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा के लिए १९,०४५.१५ करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ७,०१०.४५ करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास के लिए १५,२१५.२९ करोड़ रुपये की निधि रोक रखी है। ये केवल कुछ प्रमुख क्षेत्रों के उदाहरण हैं।

» इसी बीच, दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) द्वारा इस प्रकार जल छोड़ा जाता है कि लगभग हर वर्ष

बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य को ४०० करोड़ रुपये से अधिक की बाढ़ राहत प्रदान करने से इनकार किया है।

» केंद्र सरकार पर अभी भी चक्रवात बुलबुल, अम्फान और यस से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए ४३,५०९ करोड़ रुपये की बकाया राशि है।

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक और सांस्कृतिक विश्वासघात

» आर्थिक वंचना के अतिरिक्त, भाजपा ने बंगाल के लोकतांत्रिक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक स्थिरता को भी कमजोर करने का प्रयास किया है।

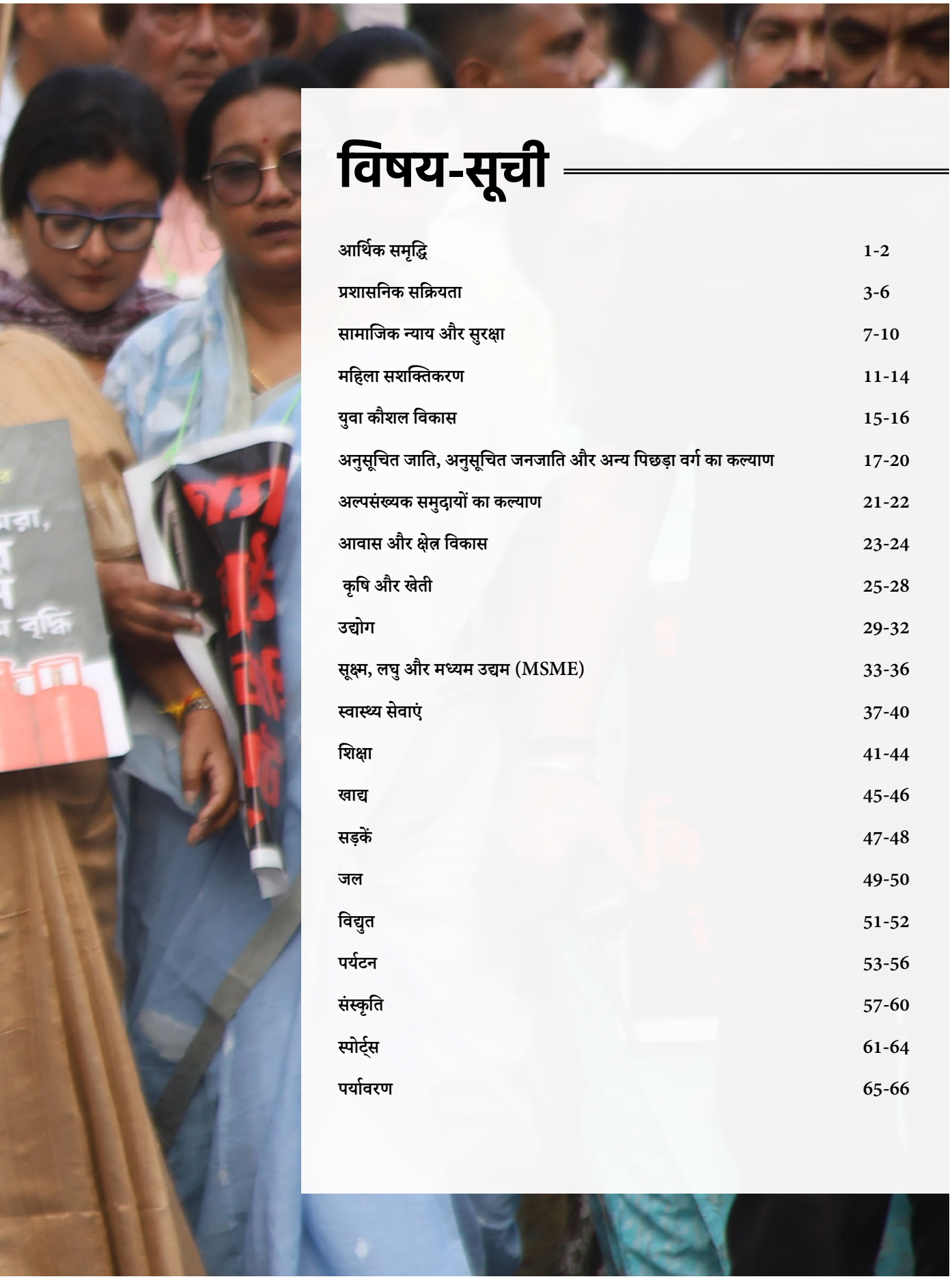
» उन्होंने बार-बार हमारे महान व्यक्तित्वों एवं विचारकों की प्रतिमाओं का विध्वंस किया, उनके नामों का विकृत उच्चारण किया तथा हमारे प्रिय कवियों और उपन्यासकारों की रचनाओं से गलत उद्धरण देकर राज्य के भाषाई एवं सांस्कृतिक गौरव के प्रति अवमानना प्रदर्शित करते हुए बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर आघात किया है।

» बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कई भाजपा-शासित राज्यों में शत्रुता का सामना करना पड़ा है और उन्हें वहां से बेदखल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने काम और आजीविका से वंचित हो गए हैं।

» भाजपा ने SIR के माध्यम से मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के मताधिकार को छीनने का प्रयास किया है, जो बंगाल के वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को सीमित कर यहां के लोकतंत्र को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है।

» इन सभी षड्यंत्रों के बावजूद, बंगाल अपनी भाषा, संस्कृति, लोकतांत्रिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा करते हुए राज्य की आवाज़ को कमजोर करने के सभी दुष्प्रयासों के विरुद्ध एकजुट होकर डटा हुआ है।





विषय-सूची

आर्थिक समृद्धि	1-2
प्रशासनिक सक्रियता	3-6
सामाजिक न्याय और सुरक्षा	7-10
महिला सशक्तिकरण	11-14
युवा कौशल विकास	15-16
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	17-20
अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण	21-22
आवास और क्षेत्र विकास	23-24
कृषि और खेती	25-28
उद्योग	29-32
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)	33-36
स्वास्थ्य सेवाएं	37-40
शिक्षा	41-44
खाद्य	45-46
सड़कें	47-48
जल	49-50
विद्युत	51-52
पर्यटन	53-56
संस्कृति	57-60
स्पोर्ट्स	61-64
पर्यावरण	65-66



१. आर्थिक समृद्धि

मुख्य उद्देश्य

- सभी क्षेत्रों में निवेश को त्वरित करके एवं अभूतपूर्व आर्थिक विकास को बनाए रखकर, अगले १० वर्षों के भीतर बंगाल को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना और अगले ५ वर्षों के भीतर ४० लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना।

- पूर्वी भारत में व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में बंगाल की स्थापना करना, इसके लिए गहरे समुद्र और नदी बंदरगाहों के नेटवर्क का विस्तार करना और आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण करना, साथ ही निर्यात बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने के लिए एक वैश्विक व्यापार केंद्र का निर्माण करना।

हमारी सफलता:

जीडीपी और मैक्रो संकेतकों में वृद्धि

» पिछले 15 वर्षों में बंगाल की नाममात्र जीडीपी लगभग 6 गुना बढ़ गई है।

» साथ ही, प्रति व्यक्ति औसत आय तीन गुना हो गई है।

» "हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक 1.72 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।"

» पिछले 15 वर्षों में बंगाल के भौतिक क्षेत्र के अवसंरचना पर खर्च में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है, जबकि बंगाल के उत्पादक पूंजीगत खर्च में लगभग 18 गुना वृद्धि हुई है।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर में गिरावट

» भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में १५ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर पिछले ६ वर्षों में ४५.६५% कम हो गई है।

राज्य द्वारा प्रदर्शित वित्तीय अनुशासन: एफआरबीएम कानून का अनुपालन

» सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा २०१०-११ में ३.७७५% से घटकर २०२६-२७ में १.०१% होने की उम्मीद है।

» सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा २०१०-११ में ४.२४% से घटकर २०२६-२७ में २.९१% होने की उम्मीद है।

» सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण २०१०-११ में ४0.६५% से घटकर २०२६-२७

» में ३७.९८% होने की उम्मीद है।

मासिक पारिवारिक खर्चों में वृद्धि

» पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) १२ वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़कर १,२९१ रुपये से ३,६२० रुपये हो गया है।

राज्य का अपना कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि:

» राज्य के अपने कर राजस्व में २०१०-११ में २१,१२९ करोड़ रुपये से बढ़कर २०२६-२७ में १,१८,६६९ करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो लगभग ६ गुना वृद्धि है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* अगले 10 वर्षों में बंगाल को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना:
पश्चिम बंगाल ने पिछले दो वित्तीय वर्षों (२०२४-२५ और २०२५-२६) में औसतन १०.५% की दर से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है। यह स्थिर वृद्धि दर बंगाल को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने में सहायक होगी। अगले ५ वर्षों में, बंगाल ४० लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा।

* पश्चिम बंगाल पूरे पूर्वी भारत के लिए 'भारत के व्यापार का प्रवेश द्वार' बनकर उभरेगा:
पूर्वी भारत के संपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में बंगाल को स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण अवसंरचना, एक वैश्विक व्यापार केंद्र, नदी और गहरे समुद्र के बंदरगाहों का एक सघन नेटवर्क और एक नया लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा, निर्यात संपर्क मजबूत होगा और बंगाल के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे।



२. प्रशासनिक सक्रियता

मुख्य उद्देश्य

- महानगर मिशन के अंतर्गत ७ नए जिलों का सृजन करके और २५ प्रमुख शहरों को अत्याधुनिक शहरी अवसंरचना से सुसज्जित आदर्श शहरों के रूप में विकसित करके प्रशासनिक और शहरी प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत करना।

- राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू करना ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एकरूपता लाई जा सके और उन्हें उचित वेतन, बेहतर क्रय शक्ति और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हमारी सफलता:

» बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने ४ नए प्रशासनिक जिले (कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम और पश्चिम बर्दवान), ४ उपमंडल (झालदा, मानबाजार, मीरिक और धूपगुड़ी) और ४ प्रशासनिक ब्लॉक (कल्याणी, लावा, पेडांग और क्रांति) गठित किए हैं। फरक्का उपमंडल जल्द ही चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए ११ विकास प्राधिकरण और २ योजना प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

» ८.०७ लाख डोरस्टेप गवर्नमेंट कैंपों के माध्यम से १०.४३ करोड़ सरकारी सेवाएं लोगों के घर-घर तक पहुंचाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, ३,५०० से अधिक बांग्ला सहायता केंद्रों के माध्यम से १५.8६ करोड़ सरकारी सेवाएं प्रदान की गई हैं।

» भारत में अपनी तरह के पहले और अभूतपूर्व 'हमारा पाड़ा, हमारा समाधान' कार्यक्रम के तहत, पश्चिम बंगाल के ८०,००० बूथों में आम लोगों ने लोकतांत्रिक रूप से स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए ८,००० करोड़ रुपये (प्रति बूथ १0 लाख रुपये) का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

» पश्चिम बंगाल सरकार ने शिकायत निवारण के लिए तकनीक-आधारित प्रणालियों के माध्यम से जन-केंद्रित शासन को सशक्त बनाया है। 'सरासरी मुख्यमंत्री' के अंतर्गत, नागरिकों को माननीय मुख्यमंत्री के साथ सीधे संवाद करने और अपनी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक सीधा माध्यम प्रदान किया गया है। ५४ विभागों और ५,८१८ कार्यालयों में कुल ६०,१४,6४४ शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से ५४,१७,८९८ शिकायतों का निवारण किया जा चुका है, जो ९०% से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है।

» कोलकाता लगातार भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। देश के सभी महानगरों में कोलकाता में अपराध दर सबसे कम है, जो मात्र ८३.९ है; यह राष्ट्रीय औसत (८२८) से काफी कम है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध दर भी सबसे कम है; २०११ में प्रति लाख जनसंख्या पर २.8 अपराध दर से घटकर २०२३ में मात्र ०.१ प्रति लाख जनसंख्या रह गई है, जो ३० गुना कम है।

» पिछले १५ वर्षों में, अधिकार क्षेत्र के दायरे को विस्तारित करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए १ पुलिस निदेशालय, ६ पुलिस आयुक्त कार्यालय, १४ पुलिस जिले, ४९ महिला पुलिस स्टेशन, ८ तटीय पुलिस स्टेशन, ३६ साइबर पुलिस स्टेशन और १०६ नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* सभी प्रमुख पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 'हाई-परफॉर्मेंस' इकाई का गठन:
  उद्देश्य - वंचित लोगों तक प्राथमिकता वाली सरकारी नीतियों के कुशल कार्यान्वयन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 'पश्चिम बंगाल उच्च प्रदर्शन वितरण इकाई' की स्थापना की जाएगी।यह इकाई मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ मिलकर काम करेगी और इसका नेतृत्व एक विशेष रूप से नियुक्त प्रधान सलाहकार करेंगे। यह इकाई आम जनता और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच एक द्विदिशात्मक संचार मंच प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर जनता की मांगों, विचारों और शिकायतों को नियमित रूप से एकत्र और विश्लेषण किया जाएगा, ताकि राज्य स्तर पर उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।

* राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा:
  राज्य सरकार जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुरूप वेतन संरचना को समायोजित करेगी, जिससे उचित वेतन, बेहतर क्रय शक्ति और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

* महंगाई भत्ता (डीए) बकाया का समयबद्ध भुगतान:
  राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, तथा पंचायतों, नगर निकायों और अन्य स्थानीय

निकायों जैसे अनुदानित संस्थानों के कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों को ROPA 2009 के अंतर्गत लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया का भुगतान मार्च 2026 से वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा।

* भौगोलिक पुनर्गठन और नगरपालिकाओं की संख्या में वृद्धि:
जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलावों के परिणामस्वरूप, कई नगर पालिकाएं अब निवासियों की अत्यधिक संख्या को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सरकारी सेवाओं की कुशल और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन के अनुपात में लोगों की आदर्श स्थिति बनाए रखने हेतु एक व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

* राज्य में सात नए जिलों का गठन किया जाएगा:
सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार लाने और मौजूदा जिला प्रशासनों पर दबाव कम करने के लिए, पश्चिम बंगाल में सात नए जिलों का गठन किया जाएगा, जिनके नाम हैं कंडी, बहरामपुर, बिष्णुपुर, सुंदरबन, राणाघाट, इचामती और बसीरहाट।

* पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'बांग्ला' करने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी:
लगभग ८0 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी, बंगाल को आज भी 'पश्चिम बंगाल' नाम से ही पुकारा जाता है, जो विभाजन की भयावहता का परिणाम है। इस समस्या के निवारण के लिए हमने बार-बार अपने राज्य का नाम बदलकर 'बांग्ला' करने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार इसमें बाधा डाली है। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'बांग्ला' नाम सुनिश्चित करने का हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

* सहभागी शासन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा:
'द्वारे सरकार', 'पाड़ाय समाधान' और 'आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बंगाल ने सहभागी प्रशासन में एक राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है। जन-केंद्रित प्रशासन को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये पहल निर्बाध रूप से चलती रहें।

* बंगाल को अप्रत्याशित बाढ़ से बचाना:
हम केंद्र सरकार के समक्ष बंगाल में अप्रत्याशित बाढ़ का मुद्दा मजबूती से उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) हमारे राज्य के लोगों के हितों, आजीविका और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक समन्वित और वैज्ञानिक जल निकासी नीति का पालन करे।

* 'मिशन महानगर' कार्यक्रम के तहत, पश्चिम बंगाल के २५ प्रमुख शहरों को अत्याधुनिक शहरी अवसंरचना के साथ मॉडल शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा:
हावड़ा, डायमंड हार्बर, बर्दवान, दुर्गापुर, बोलपुर, कृष्णानगर, बारासात, रायगंज, सिलीगुड़ी, बेरहामपुर, मालदा, कल्याणी, श्रीरामपुर, अंडाल, बांकुरा, पुरुलिया, दीघा, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, एनकेडीए क्षेत्र, गंगारामपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग को अत्याधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के साथ मॉडल शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।





३. सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा

प्रमुख लक्ष्य:

- सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक 'गिग वर्कर्स नीति' लागू की जाएगी तथा सभी पंजीकृत गिग श्रमिकों को निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।

- राज्य के सभी जॉब कार्ड धारकों के लिए महात्मा-श्री योजना के अंतर्गत १०० दिनों का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ:

» जय बांग्ला योजना के तहत,२०.५७ लाख विधवाओं, ५०.६१ लाख वरिष्ठ नागरिकों, ७.५९ लाख दिव्यांगजनों और २.१२ लाख अन्य लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिल रही है, जिसके लिए वार्षिक आवंटन १०,५७३.८७ करोड़ रुपये है।

» नि:शुल्क सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, १.८४ करोड़ असंगठित श्रमिकों को २,८८० करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, जिससे उनके लिए चिकित्सा, मृत्यु और कल्याणकारी लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।

» २०२३ में शुरू की गई कर्मसाथी (प्रवासी श्रमिक) योजना हमारे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा करती है और उनकी शिकायतों का समाधान करती है, जबकि श्रमश्री (२०२५) योजना ३१.७७ लाख वापस लौटने वाले श्रमिकों को नई नौकरी मिलने तक प्रति माह ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्हें जॉब कार्ड, कौशल विकास, राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं।

» बंगाल केंडू लाइव्स कलेक्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम से ३५,००० लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जनजाति के हैं। यह योजना पंजीकृत कलेक्टरों को ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।इसके अलावा, कलेक्टर आकस्मिक मृत्यु, मातृत्व लाभ, शारीरिक विकलांगता लाभ, स्वास्थ्य सहायता आदि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर की मृत्यु होने पर, उनके नॉमिनी को मृत्यु लाभ के साथ-साथ अंतिम संस्कार सहायता भी मिल सकती है।

» जब १०० दिनों के काम के लिए केंद्रीय निधि (एमजीएनआरईजीए) आना बंद हो गई, तो हमने कर्मश्री योजना (अब महात्मा-श्री) शुरू की, जिसने २०,७७६ करोड़ रुपये की लागत से ७८.३१ लाख से अधिक जॉब कार्ड धारकों के लिए १०४.५८ करोड़ कार्य दिवस सृजित किए हैं।

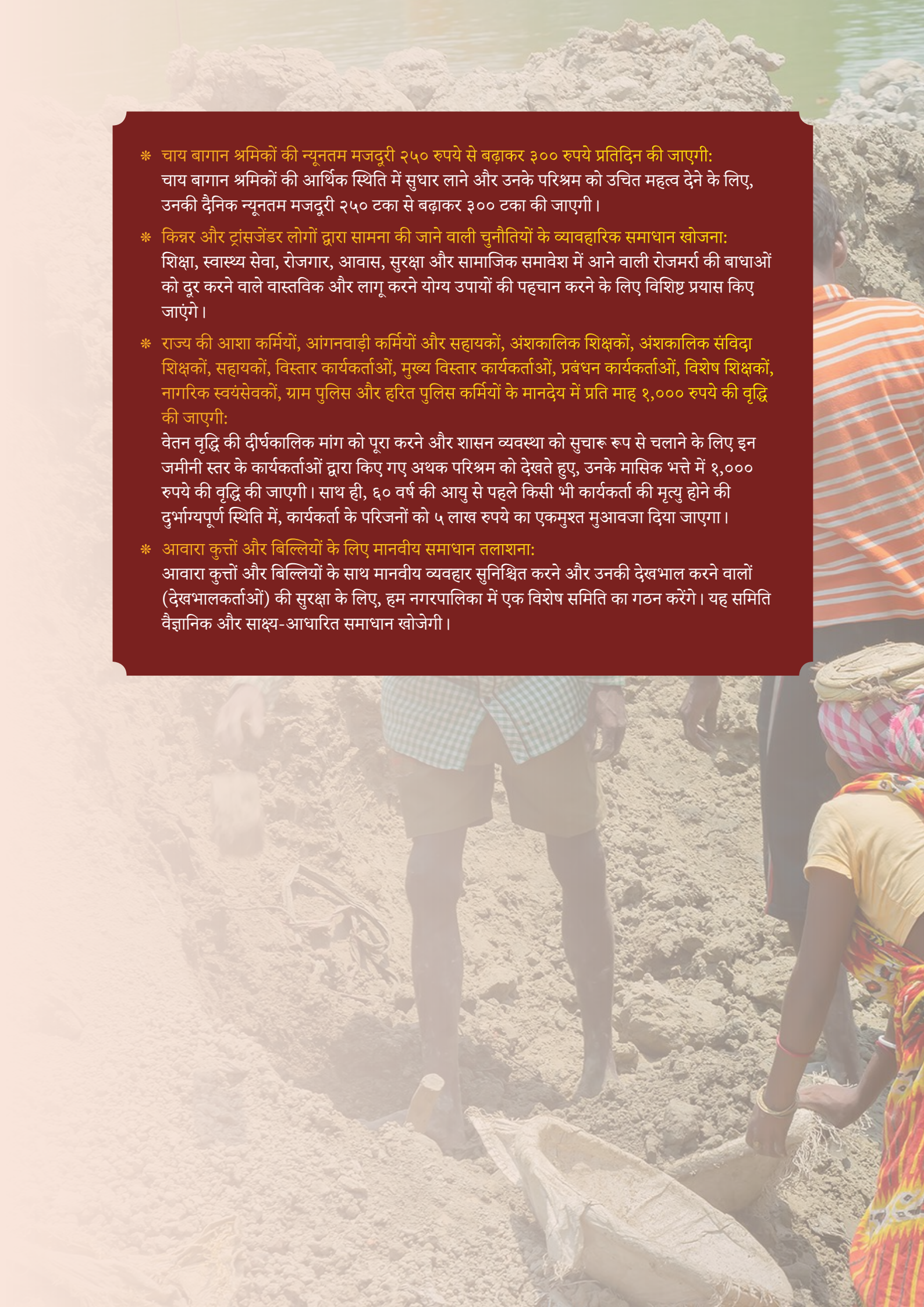
आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* वृद्धावस्था भत्ता सुरक्षा को मजबूत और विस्तारित करना:
  सभी वर्तमान लाभार्थियों के लिए निर्बाध वृद्धावस्था भत्ता सहायता सुनिश्चित करने के अलावा, हम धीरे-धीरे इस भत्ते के दायरे को सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित करेंगे; ताकि बंगाल के वरिष्ठ नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

* गिग वर्कर्स के लिए एक नई नीति लागू की जाएगी और उन्हें व्यापक सुरक्षा जाल के अंतर्गत लाया जाएगा:
  गिग वर्कर्स के लिए एक विशिष्ट नीतिगत ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके तहत गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और सरकार के प्रतिनिधियों वाला एक बोर्ड गठित किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक पंजीकृत गिग वर्कर को निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

* पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक आर्थिक सहायता में ५०० रुपये की वृद्धि:
  पुरोहितों और मुअज्जिनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को और सुदृढ़ करने के लिए, वर्तमान में दी जा रही १,५०० रुपये की मासिक सहायता को बढ़ाकर २,००० रुपये (वार्षिक २४,००० रुपये) किया जाएगा।

* राज्य सरकार महात्मा श्री पहल के तहत राज्य के सभी जॉब कार्ड धारकों को १०० दिनों का काम उपलब्ध कराएगी:
  केंद्र सरकार ने १०० दिन की कार्य योजना रद्द कर दी है। इसे देखते हुए, बंगाल के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार सभी जॉब कार्ड धारकों को १०० दिनों का काम गारंटी के साथ प्रदान करेगी।



* चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी २५० रुपये से बढ़ाकर ३०० रुपये प्रतिदिन की जाएगी:
  चाय बागान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके परिश्रम को उचित महत्व देने के लिए, उनकी दैनिक न्यूनतम मजदूरी २५० टका से बढ़ाकर ३०० टका की जाएगी।
* किन्नर और ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान खोजना:
  शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवास, सुरक्षा और सामाजिक समावेश में आने वाली रोजमर्रा की बाधाओं को दूर करने वाले वास्तविक और लागू करने योग्य उपायों की पहचान करने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे।
* राज्य की आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों, अंशकालिक शिक्षकों, अंशकालिक संविदा शिक्षकों, सहायकों, विस्तार कार्यकर्ताओं, मुख्य विस्तार कार्यकर्ताओं, प्रबंधन कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षकों, नागरिक स्वयंसेवकों, ग्राम पुलिस और हरित पुलिस कर्मियों के मानदेय में प्रति माह १,००० रुपये की वृद्धि की जाएगी:
  वेतन वृद्धि की दीर्घकालिक मांग को पूरा करने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अथक परिश्रम को देखते हुए, उनके मासिक भत्ते में १,००० रुपये की वृद्धि की जाएगी। साथ ही, ६० वर्ष की आयु से पहले किसी भी कार्यकर्ता की मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, कार्यकर्ता के परिजनों को ५ लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा।
* आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए मानवीय समाधान तलाशना:
  आवारा कुत्तों और बिल्लियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने और उनकी देखभाल करने वालों (देखभालकर्ताओं) की सुरक्षा के लिए, हम नगरपालिका में एक विशेष समिति का गठन करेंगे। यह समिति वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित समाधान खोजेगी।





४. महिला सशक्तिकरण

मुख्य उद्देश्य

- लक्ष्मी भंडार योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर १,७०० रुपये प्रति माह (२०,४०० रुपये प्रति वर्ष) और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए १,५०० रुपये प्रति माह (१८,००० रुपये प्रति वर्ष) कर दी जाएगी, जिससे पारिवारिक आय में वृद्धि होगी।

- रोज़गार और व्यावसायिक अवसरों के विस्तार एवं स्वयं सहायता समूहों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से, अगले ५ वर्षों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर को ४४.७% से बढ़ाकर ५०% तक पहुँचाया जाएगा।

हमारी सफलता:

» लक्ष्मी भंडार योजना के तहत २.४ करोड़ महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

» कन्याश्री प्रकल्प के तहत १८,००० संस्थानों के माध्यम से १ करोड़ बेटियाँ लाभान्वित हुई हैं।

» रूपश्री प्रकल्प' के तहत २२ लाख से भी अधिक महिलाओं को उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

» राज्य में २० लाख से भी अधिक विधवा महिलाओं को पेंशन प्राप्त होती है।

» सबुजश्री प्रकल्प के तहत, नवजातों की माताओं को ६८ लाख पौधे वितरित किए गए हैं।

» महिला स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर है, जहाँ कुल ३१ लाख महिला उद्यमी हैं।

» स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि २०१०-११ में ५३१ करोड़ रुपये से बढ़कर २०२५-२६ में ३५,००० करोड़ रुपये हो गई है, जो लगभग ७० गुना अधिक है।

» आनंदधारा प्रकल्प के माध्यम से १.२१ करोड़ महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं।

» स्वयं सहायता समूहों की संख्या २०१०-११ में लगभग १ लाख से १२ गुना बढ़कर २०२५-२६ में १२ लाख से भी अधिक हो गई है।

» स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत ५ लाख महिलाओं को पोशाक और यूनिफॉर्म बनाने के कार्य में नियुक्त किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप १.५ करोड़ कार्यदिवस सृजित हुए हैं।

» महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में और अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, २०२४ में हमारी सरकार ने अपराजिता बिल पेश किया।

» तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया 'रात्तिरेर साथी' ऐप, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली या अंधेरा होने के बाद यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए संकट के समय तत्काल सहायता सुनिश्चित करता है।

» बंगाल की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ५१.४% है, जो कि ४५.६% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

» बंगाल में संस्थागत प्रसव की दर अब ९९.१३% है, जो लगभग सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* सभी महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाकर पारिवारिक आय में वृद्धि करना:
सभी महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाकर पारिवारिक आय में वृद्धि करना: परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करने और पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए, सभी वर्गों के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में ५०० रुपये की वृद्धि की गई है। अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को १,७०० रुपये प्रति माह और सामान्य वर्ग की महिलाओं को १,५०० रुपये प्रति माह मिलेंगे।

* राज्य पुलिस बल में महिला कर्मियों का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जाएगा:
राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सहानुभूतिपूर्ण पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए।

* कर्मंजलि योजना के तहत, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कामकाजी महिला छात्रावास होगा:
राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जिले

में कम से कम एक कामकाजी महिला छात्रावास हो।

* अपराजिता विधेयक के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम:
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत और पारित ऐतिहासिक अपराजिता विधेयक के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी जल्द से जल्द प्राप्त करने हेतु प्रयास और संघर्ष तेज किए जाएंगे।

* "रात्तिरेर साथी" ऐप को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जाएगा: इसे उपयोग में आसान और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

* महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

* महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना:
पर्याप्त रोजगार और उद्यमिता के अवसर सृजित करके, पश्चिम बंगाल में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी अगले ५ वर्षों में ४४.७% से बढ़ाकर ५०% की जाएगी।

* अगले ५ वर्षों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या और स्वयं सहायता समूह आधारित ऋणों के वितरण में वृद्धि की जाएगी।
स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कार्यस्थलों पर कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध ऋण राशि भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देगी।

* स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए विपणन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर ५० की जाएगी।
इससे मौजूदा स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के विपणन केंद्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिससे प्रत्येक जिले में कम से कम २ केंद्र सुनिश्चित हो जाएंगे।





५. युवा शक्ति का कौशल विकास

मुख्य उद्देश्य

- २१ से ४० वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक बांग्ला युवा साथी योजना के तहत प्रति माह १,५०० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- राज्य भर में विभिन्न बड़े पैमाने की औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से १० लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

हमारी उपलब्धियाँ:

» राज्य में बेरोजगारी २०११ से ४०% कम हुई है।

» 'मा-माटी-मानुष' की सरकार के तहत बंगाल में २ करोड़ से भी अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं।

» युवा कल्याण एवं खेल विभाग का बजट पिछले १५ वर्षों में सात गुना बढ़ा है, जो बंगाल में युवा एवं खेल विकास पर निरंतर और रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

» २०११ से अब तक कुल ४४ युवा छात्रावासों का नवनिर्माण या जीर्णोद्धार किया गया है।

» हमारी सरकार ने ९१२ युवा कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या २०११ में ६५ से बढ़कर २०२६ में ३५७ हो गई है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या २०११ में ८० से बढ़कर २०२६ में ३१७ हो गई है।

» उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के तहत रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, और इस परियोजना के तहत ४.६ मिलियन युवाओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है।

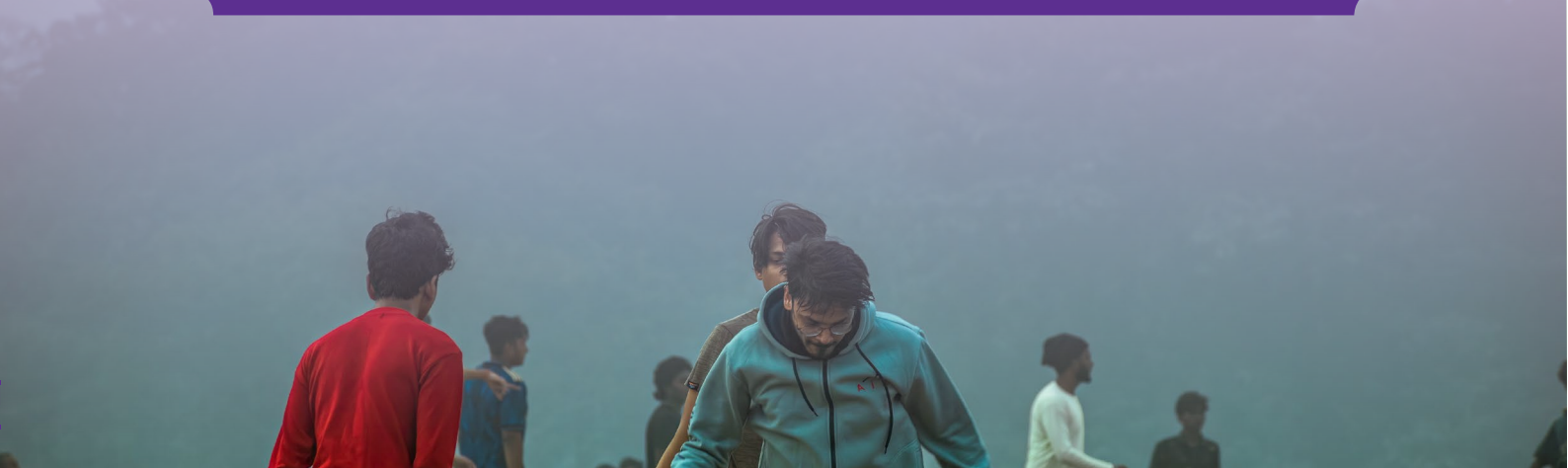
आने वाले वर्षों में हम जो कार्य करने का वादा करते हैं:

* राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए १,५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता (बांग्लार युवा साथी):
  २१ से ४० वर्ष की आयु के सभी बेरोजगार युवा, जिन्होंने कक्षा १० उत्तीर्ण की है और अभी तक रोजगार नहीं पाया है, उन्हें अधिकतम ५ वर्षों तक या रोजगार मिलने तक (जो भी पहले हो) १,५०० रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

* बंगाल की क्रिएटिव इकोनॉमी को गति देना:
  रचनात्मक उद्योगों की अपार क्षमता का दोहन करने के लिए एक विशेष नीति लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य रचनाकारों को पूंजी या ऋण उपलब्ध कराना, आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, वैश्विक ख्याति के लिए मार्ग प्रशस्त करना और उनके बौद्धिक एवं रचनात्मक अधिकारों की रक्षा करना है; ताकि यह रचनात्मक कार्य रोजगार सृजित करे, नए व्यवसाय विकसित हों और हमारी संस्कृति का प्रभाव विश्वभर में फैले ।

* राज्य में 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे:
  पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न पहल, जैसे देउचा पंचमी में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान, पुरुलिया में जंगलसुंदरी कर्मनगरी नामक एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक पार्क, 6 नए औद्योगिक गलियारे (रघुनाथपुर-ताजपुर, दनकुनी-कल्याणी, दनकुनी-झारग्राम, दनकुनी-कोचबिहार, खड़गपुर-मोर्ग्राम, पुरुलिया में गुरुडी से कोलकाता में जोका तक), कर्मदिगांटा लेदर पार्क और सागरदिघी सुपरक्रिटिकल ऊर्जा इकाई राज्य में कम से कम 10 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा करेगी.

* हम सभी सरकारी रिक्तियों को व्यवस्थित तरीके से भरने का प्रयास करेंगे:
  हमारा लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों में शेष सभी रिक्त पदों को व्यवस्थित तरीके से भरना है ताकि युवाओं को सुरक्षित सरकारी रोजगार प्रदान किया जा सके।





६. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

मुख्य उद्देश्य

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, जिसके लिए पूर्णतः डिजिटल और समयबद्ध सेवा वितरण के माध्यम से १००% छात्रवृत्ति का प्रावधान सुनिश्चित करना, प्रत्येक ब्लॉक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों का विस्तार करना और योगाश्री कोचिंग प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

- महतो समुदाय और किसान जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयासों को मजबूत किया जाए; साथ ही सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीएस) के माध्यम से स्वदेशी स्वयं सहायता समूहों के लिए संस्थागत समर्थन बढ़ाया जाए और संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए अनुसूचित मित्र सहायता प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाए।

हमारी उपलब्धियाँ:

» पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित १.६९ करोड़ से अधिक लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

» अधिक पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर २०२२ से डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड वाले जाति प्रमाण पत्र शुरू किए
गए हैं।

» जय जोहार और अनुसूचित बंधु योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के १४.६४ लाख लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान की गई है।

» पिछले १५ वर्षों में, लगभग १,२७,५०० अनुसूचित जाति के युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों में अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

» अनुसूचित जाति परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेरिट अवार्ड और ठाकुर हरिचंद गुरचंद अवार्ड शुरू किए
गए हैं।

» पिछले 15 वर्षों में, राज्य में अनुसूचित जाति के ३०,९०,४६२ छात्रों और अन्य पिछड़ा वर्ग के ३५,०९,९७२ छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है।

» २०११ से अब तक ६४,६८,४०० अनुसूचित जाति के छात्रों और २९,२५,९२० अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं।

» शिक्षा श्री छात्रवृत्ति योजना के तहत १,२५,५०,८२८ अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिला है।

» राज्य सरकार ने लेपचा, तमांग, भूटिया, शेरपा, लिंबू, लोढ़ा-शाबर और भूमिज समुदायों के लिए विकास और सांस्कृतिक बोर्डों का गठन किया है।

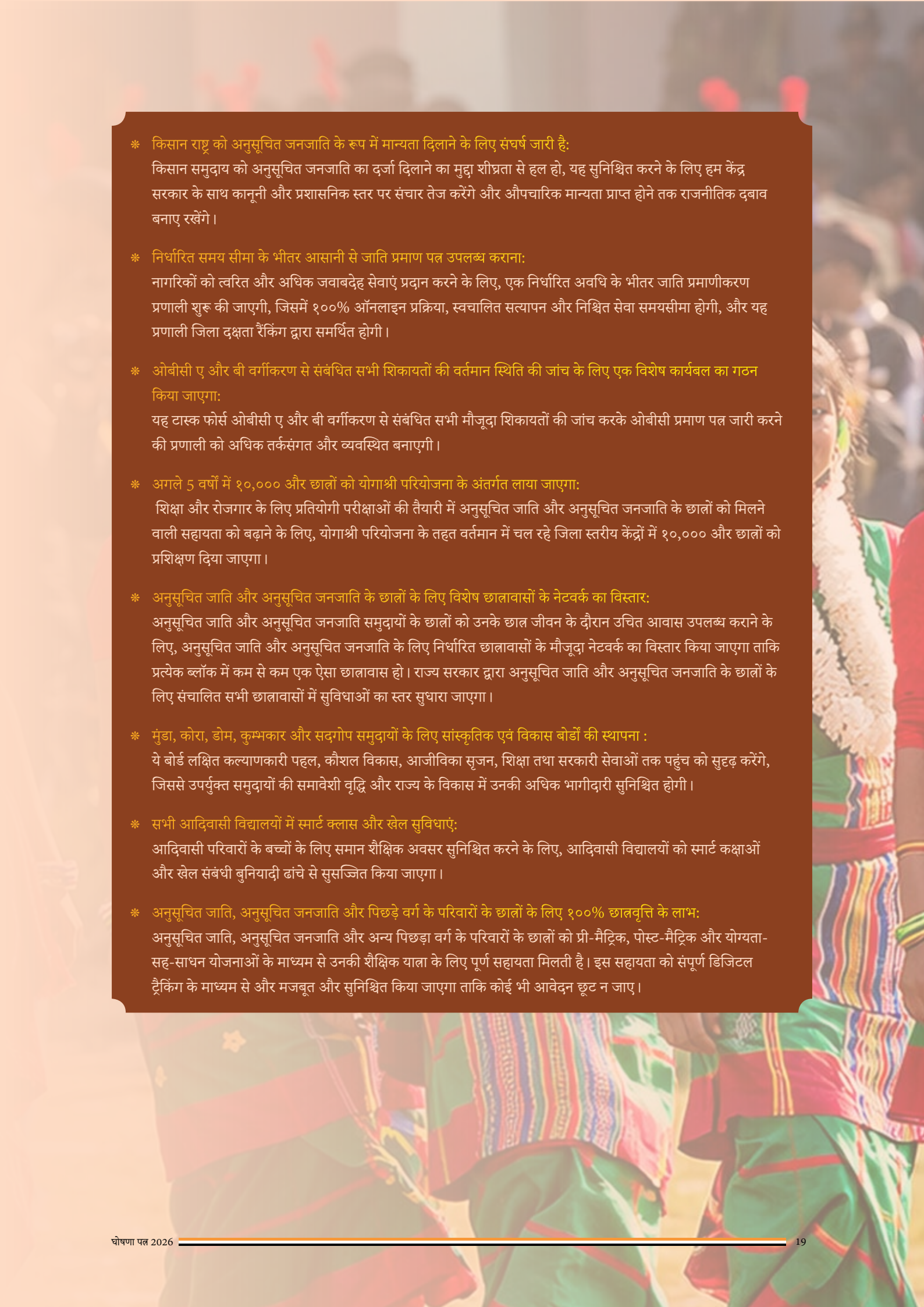
» आदिवासियों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए, हमारी सरकार ने ७४८ जाहेर थानों के संरक्षण और १,५३७ मांझी थानों के निर्माण में सहयोग दिया है।

» बड़े क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों/सहकारी समितियों (एलएएमपीएस) के अंतर्गत ८,३१४ आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों को परिक्रामी निधि की सुविधा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध हैं:

* स्वदेशी नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीएस) को मजबूत करना:
एलएएमपीएस के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा ताकि इसके सदस्यों के सामाजिक विकास और आजीविका सृजन में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, एलएएमपीएस के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक समर्पित परिक्रामी निधि से उनकी आजीविका में सुधार होगा और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनके समावेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

* महातो समुदाय की अनुसूचित जनजाति मान्यता की लड़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना:
हम महतो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अपनी सिफारिश पर भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वह मान्यता और सरकारी सहायता योजनाओं के लाभ प्राप्त हों जिनके वे हकदार हैं।



* किसान राष्ट्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष जारी है:
  किसान समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का मुद्दा शीघ्रता से हल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम केंद्र सरकार के साथ कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर संचार तेज करेंगे और औपचारिक मान्यता प्राप्त होने तक राजनीतिक दबाव बनाए रखेंगे।

* निर्धारित समय सीमा के भीतर आसानी से जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना:
  नागरिकों को त्वरित और अधिक जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक निर्धारित अवधि के भीतर जाति प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसमें १००% ऑनलाइन प्रक्रिया, स्वचालित सत्यापन और निश्चित सेवा समयसीमा होगी, और यह प्रणाली जिला दक्षता रैंकिंग द्वारा समर्थित होगी।

* ओबीसी ए और बी वर्गीकरण से संबंधित सभी शिकायतों की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा:
  यह टास्क फोर्स ओबीसी ए और बी वर्गीकरण से संबंधित सभी मौजूदा शिकायतों की जांच करके ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली को अधिक तर्कसंगत और व्यवस्थित बनाएगी।

* अगले 5 वर्षों में १०,००० और छात्रों को योगाश्री परियोजना के अंतर्गत लाया जाएगा:
  शिक्षा और रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली सहायता को बढ़ाने के लिए, योगाश्री परियोजना के तहत वर्तमान में चल रहे जिला स्तरीय केंद्रों में १०,००० और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष छात्रावासों के नेटवर्क का विस्तार:
  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को उनके छात्र जीवन के दौरान उचित आवास उपलब्ध कराने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित छात्रावासों के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा छात्रावास हो। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संचालित सभी छात्रावासों में सुविधाओं का स्तर सुधारा जाएगा।

* मुंडा, कोरा, डोम, कुम्भकार और सदगोप समुदायों के लिए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों की स्थापना :
  ये बोर्ड लक्षित कल्याणकारी पहल, कौशल विकास, आजीविका सृजन, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सुदृढ़ करेंगे, जिससे उपर्युक्त समुदायों की समावेशी वृद्धि और राज्य के विकास में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

* सभी आदिवासी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और खेल सुविधाएं:
  आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए, आदिवासी विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया जाएगा।

* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए १००% छात्रवृत्ति के लाभ:
  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के छात्रों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और योग्यता-सह-साधन योजनाओं के माध्यम से उनकी शैक्षिक यात्रा के लिए पूर्ण सहायता मिलती है। इस सहायता को संपूर्ण डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से और मजबूत और सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोई भी आवेदन छूट न जाए।



* राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में अनुसूचित सहायता प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा:
बीडीओ (या शहरी क्षेत्रों के लिए एसडीओ) इस अनुसूचित सहायता प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करेंगे और इसमें बीएल एंड एलआरओ कार्यालय, बीसीडब्ल्यू, इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।इसके अलावा, आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करेगा, कानूनी प्रावधानों या नियमों और विनियमों पर जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लाभों तक पहुंच को सुगम बनाएगा आदि। इन प्रकोष्ठों के कामकाज की निगरानी मासिक आधार पर संबंधित क्षेत्र के एसडीओ द्वारा और पूरे जिले के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशिष्ट ढांचे के माध्यम से की जाएगी।



७. अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण

मुख्य उद्देश्य

- समुदाय के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी शामिल है।

- अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आलिया विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुखी नए पाठ्यक्रम शुरू करके और २७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अल्पसंख्यक युवाओं के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना।

हमारी उपलब्धियाँ:

» ऐक्यश्री योजना के माध्यम से ४.९५ करोड़ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा संचालित सबसे बड़ी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना है।

» बेसहारा अल्पसंख्यक महिला पुनर्वास कार्यक्रम (डीएमडब्ल्यूआरपी) के माध्यम से २,६०,०२७ बेसहारा अल्पसंख्यक महिलाओं को आवास सुनिश्चित किया गया है। इस वर्ष ३३,७५३ आवास इकाइयों को भी स्वीकृत किया गया है।

» अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई में सहायता के लिए मदरसों में १,२०० स्मार्ट क्लासरूम, ११५ डिजिटल लैब और ७६ विज्ञान प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

» आलिया विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में छात्रावासों के बुनियादी ढांचे के व्यापक उन्नयन की शुरुआत की गई है।

» अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित करने में पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर है।

» अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट लगभग दस गुना बढ़ा दिया गया है।

» सरकार ने लगभग १,३८७ करोड़ रुपये के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण के लिए 1,387 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

» हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं में आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ३,९०० करोड़ रुपये का निवेश किया है।

» अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के लिए २७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और ५ पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए गए हैं।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

❋ वक्फ संपत्ति का संरक्षण और प्रभावी उपयोग:
समुदाय के सामान्य कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य भर में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, विकास और उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी शामिल है।

❋ आलिया विश्वविद्यालय में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का विस्तार:
आलिया विश्वविद्यालय में एलएलबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरामेडिक और एम.एड. जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर और अधिक बढ़ेंगे।

❋ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा:
राज्य में मौजूद कौशल अंतर को दूर करने और अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के २७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

❋ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष सांस्कृतिक केंद्र:
राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में सहायता के लिए विशेष सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।





८. आवास एवं क्षेत्र का विकास

मुख्य उद्देश्य

३० लाख और परिवारों को सहायता प्रदान कर, अगले ५ वर्षों के भीतर पक्के मकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे राज्य के सभी परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी सफलता:

» पिछले १५ वर्षों में पश्चिम बंगाल में १ करोड़ परिवारों को सम्मानजनक आवास प्राप्त हुआ है।

» पूर्णतः मा-माटी-मानुष सरकार के वित्तपोषण से संचालित 'बांग्लार बाड़ी (ग्रामीण)' परियोजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल में १२ लाख परिवारों को १४,४०० करोड़ रुपये की लागत से आवास उपलब्ध कराया गया है। 'बांग्लार बाड़ी बाड़ी (ग्रामीण)' परियोजना के द्वितीय चरण में और २० लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई है, जिसके लिए १९,७०० करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाएगा।

» शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग १८,००० करोड़ रुपये की लागत से ५.२० लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है।

» पश्चिम बंगाल सरकार की 'चाय सुंदरी' एवं 'चाय सुंदरी विस्तार' योजनाओं के माध्यम से २८,५०० से अधिक चाय बागान श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराया गया है।

» गीतांजलि योजना के तहत ३,५०० करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग ३.८४ लाख मकान उपलब्ध कराए गए हैं।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्यों को करने का संकल्प लेते हैं:

* अगले ५ वर्षों में प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करना:
  पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले १५ वर्षों में लगभग १ करोड़ मकान उपलब्ध कराए हैं और अगले ५ वर्षों में ३० लाख परिवारों को मकान निर्माण हेतु सहायता प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सभी २.५ करोड़ परिवारों के सिर पर छत हो।

* एक समग्र क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ: प्रत्येक मोहल्ले या क्षेत्र को स्वच्छ, हरित एवं जीवंत सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित करने हेतु एक जन-केंद्रित क्षेत्र पुनर्नवीनीकरण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत लैंडस्केप पार्क, पैदल मार्ग, सौंदर्यीकृत सड़कें, खेल के मैदान, ओपन-एयर जिम, नर्सरी, भित्ति चित्र (म्यूरल) तथा सामुदायिक प्लाजा का निर्माण किया जाएगा।

* उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता:
  विभिन्न नगरपालिकाओं में ९ नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा पूरे बंगाल में अधिक स्वच्छ एवं हरित क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना अपनाई जाएगी।





९. कृषि और खेती

मुख्य उद्देश्य

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ३०,००० करोड़ रुपये का एक अलग कृषि बजट शुरू किया जाएगा, जिसमें भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए ४,००० रुपयेकी वार्षिक सहायता और कृषि परिवारों को निरंतर समर्थन के साथ-साथ इस क्षेत्र का समग्र विकास शामिल है।

- किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, फसल कटाई के बाद की व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा, साथ ही धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाकर २,५०० रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। इस अवसंरचना विकास में ५० नए शीत भंडारण संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है।

हमारी सफलता:

» राज्य में कृषकबंधु (नई) योजना के माध्यम से १.१ करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

» बंगाल में सिंचाई कार्य का दायरा बढ़ाकर कृषि योग्य भूमि के लगभग ६५% तक कर दिया गया है।

» राज्य का कृषि क्षेत्र में व्यय पिछले १५ वर्षों में ९.१६ गुना बढ़ गया है।

» सरकार ने सीधे तौर पर 5५५ लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जिससे १६ लाख लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ हुआ है।

» कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मृदा सृजन योजना के तहत ४२,००० एकड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।

» २०२१ से हमारे राज्य में किसानों की आत्महत्या का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

» फसल सघनता (१९४%) और धान उत्पादन (२५६ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष) के मामले में हमारा राज्य देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा, जूट उत्पादन में हमारा राज्य देश में पहले स्थान पर है और आलू, सब्जियों, चाय, मछली और मांस उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

» देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मक्का और चावल की उत्पादकता में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है।

» राज्य समर्थित कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देने के कारण, बंगाल में कृषि के लिए ऊर्जा की उपलब्धता पिछले १५ वर्षों में १.३७ किलोवाट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर २.४७ किलोवाट हो गई है।

» फसल कटाई के बाद भंडारण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने वाली शीत भंडारण सुविधाओं की संख्या के मामले में हमारा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है।

» मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के मौसम के दौरान, हमने समुद्र साथी योजना के तहत समुद्री मछुआरों को ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

» हमने राज्य में 85 चाय बागानों को पुनः खोलने का आश्वासन दिया है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

❋ अगले वित्तीय वर्ष में ३०,००० करोड़ रुपये का एक विशिष्ट कृषि बजट प्रस्तुत किया जाएगा:
अगले वित्तीय वर्ष से एक विशिष्ट कृषि बजट लागू किया जाएगा, जो कृषि और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित प्रावधान करेगा:

- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष ४,००० रुपये की वित्तीय सहायता।
- सरकारी ट्यूबवेल और रिवर लिफ्ट सिंचाई (आरएलआई) के उपयोग पर सिंचाई शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा ।
- इस क्षेत्र में सभी मौजूदा योजनाओं और सहायता तंत्रों को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाया जाएगा।

❋ धान का खरीद मूल्य बढ़ाकर २,५०० रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है:
धान की सरकारी खरीद दर को मौजूदा २,३६९ रुपये से बढ़ाकर २,५०० रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा, ताकि किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा अतिरिक्त लाभ मिल सके। इसके अलावा, विकेंद्रीकृत धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और किसानों की डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा।समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को गरीबी के कारण अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके अलावा, निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चावल के प्रसंस्करण हेतु विशेष पहल की जाएगी।

❋ मक्का और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और खेती में विविधता लाना:
राज्य की बढ़ती मांग को पूरा करने और उत्पादन में शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, मक्का, तिलहन और अनाज की खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे खेती में विविधता आएगी। आलू, संकर मक्का, दालें और उच्च गुणवत्ता वाले तिलहन के स्थानीय उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

❋ बागवानी के बाद की फसलों के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण:
कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी; विशेष रूप से बागवानी फसलों, फलों और सब्जियों के मामले में, ताकि किसानों की आय और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में और सुधार हो सके।

❋ राज्य में ५० नए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे:
पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य भर में उपयुक्त स्थानों पर पीपीपी मॉडल के तहत ५० नए कोल्ड स्टोरेज संयंत्र स्थापित करेगी, ताकि राज्य की अतिरिक्त कृषि उपज और बागवानी फसलों का भंडारण किया जा सके। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित होगी।

❋ ग्रीन चाय की पत्तियों पर कृषि आयकर छूट २०२७ तक:
राज्य में छोटे चाय बागान मालिकों के हित में, ग्रीन चाय की पत्तियों पर कृषि आयकर छूट की अवधि एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, २०२७ तक कर दी गई है। इसके साथ ही, चाय उत्पादन पर उपकर छूट का लाभ भी 31 मार्च, २०२७ तक जारी रहेगा।

❋ डायमंड हार्बर में हिलसा मछली का केंद्र स्थापित किया जाएगा:
पश्चिम बंगाल का हिलसा मछली से गहरा सांस्कृतिक संबंध है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के अनसुलझे समझौते के कारण बंगाल को अपनी प्रिय हिलसा मछली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए डायमंड हार्बर में हिलसा मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। मछुआरों को इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जाएगी।





१०. उद्योग

मुख्य लक्ष्य:

- पांच नए मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना तथा माल परिवहन के प्रवेशद्वार के रूप में राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए, वर्ष २०३१ तक बंगाल को ३० अरब अमेरिकी डॉलर के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

- एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति तथा लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से आगामी पाँच वर्षों में बंगाल के निर्यात को दोगुना कर, वर्ष २०३०–३१ तक माल निर्यात को १७ अरब अमेरिकी डॉलर (१.५४ लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाया जाएगा।

हमारी सफलता:

» पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रमुख सीमेंट केंद्र बनकर उभरा है। राज्य में ३० से अधिक बड़े सीमेंट कारखाने कार्यरत हैं। बंगाल अब हरित सीमेंट उत्पादन में अग्रणी बन चुका है।

» देश के सबसे बड़े लेदर कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़े गारमेंट क्लस्टर, सबसे बड़े होज़री पार्क, सबसे बड़े फाउंड्री पार्क तथा एक अग्रणी रेलवे विनिर्माण हब के साथ हम एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरे हैं।

» इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग में तीव्र विस्तार देखा गया है। वित्त वर्ष २०२४ में इस्पात उत्पादन ११ मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो वार्षिक लगभग १२% की दर से बढ़ रहा है। इस्पात अब राज्य के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से एक है।

» वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में २०० से अधिक औद्योगिक पार्क कार्यरत हैं, जो एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और विश्व स्तरीय ब्रांडों को आकर्षित कर रहे हैं।

» अप्रैल से अक्टूबर २०२५ की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (विनिर्माण) की वृद्धि दर ५.८% है, जो राष्ट्रीय स्तर की वृद्धि दर ३.९% से काफी अधिक है।

» तेज़ आर्थिक विकास के लिए, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में ६ नए आर्थिक गलियारे विकसित किए हैं (रघुनाथपुर-ताजपुर, डंकुनी-कल्याणी, डंकुनी-झारग्राम, डंकुनी-कोचबिहार, खड़गपुर-मोरग्राम, पुरुलिया के गुरुदी से कोलकाता के जोका तक)।

» बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वच्छ ईंधन के रूप में कोल बेड मीथेन का दोहन करता है और बहुत जल्द हम शेल गैस का दोहन करने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ाने के लिए अशोकनगर में एक प्राकृतिक गैस निष्कर्षण संयंत्र भी बनाया जा रहा है। सक्रिय पंजीकृत कंपनियों के मामले में हमारा राज्य दूसरे स्थान पर है,

» बंगाल में प्रति कारखाने का औसत लाभ पिछले १५ वर्षों में ५.४६ गुना बढ़ गया है।

» राज्य के आईटी क्षेत्र में विभिन्न आईटी और आईटीईएस कंपनियों में २ लाख से अधिक युवा कार्यरत हैं।

» विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान, देउचा पंचमी, बीरभूम में बनाई जा रही है, जिससे १ लाख रोजगार सृजित होंगे।

» पुरुलिया का जंगल-सुंदरी वर्क सिटी ७.७५ लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार है। ३०,००० करोड़ रुपये के निवेश और ७५,००० आईटी कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाली बंगाल की सिलिकॉन वैली हमारे डिजिटल भविष्य को आकार दे रही है।

» ३०,००० करोड़ रुपये के निवेश और ७५,००० आईटी कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाली बंगाल की सिलिकॉन वैली हमारे डिजिटल भविष्य को आकार दे रही है।

» बंगाल भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर हब में से एक के रूप में उभर रहा है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

❋ बंगाल को भारत के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में बढ़ावा देना:

पश्चिम बंगाल में कम से कम ५ नए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र २०३१ तक ३० अरब डॉलर की संपत्ति बन जाए। पश्चिम बंगाल की रणनीतिक स्थिति और व्यापक सड़क संपर्क माल के भंडारण और आवागमन को सुगम बनाते हैं।

* पश्चिम बंगाल सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में उभरेगा:

भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ बनकर, पश्चिम बंगाल अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, विश्वसनीय बिजली प्रणाली, हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं और सक्रिय निवेश नीतियों का लाभ उठाएगा।

* अगले पांच वर्षों में बंगाल का निर्यात दोगुना हो जाएगा:

पश्चिम बंगाल निर्यात विकास नीति और पश्चिम बंगाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर विकास नीति को लागू करके, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के कुल वार्षिक निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी २०३१ तक दोगुनी हो जाए। २०३०-३१ तक, माल निर्यात बढ़कर १७ अरब अमेरिकी डॉलर (१,५४,२८८ करोड़ रुपये) हो जाएगा, जबकि आईटी, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक क्षमता केंद्र निर्यात वृद्धि के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे।

* बंगाल के औद्योगिक और कॉर्पोरेट क्षेत्र का विस्तार:

२०३० तक, पंजीकृत कंपनियों की संख्या बढ़कर ३,००,००० और कारखानों की संख्या बढ़कर ११,००० हो जाएगी।

* समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और निवेश राशि को शीघ्रता से बुनियादी ढांचे में परिवर्तित करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (बांग्ला औद्योगिक त्वरक) का गठन किया जाएगा:

यह विशेष प्रयोजन वाहन त्वरित अनुमोदन, जिला स्तरीय समर्थन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और नियमित निगरानी एवं त्रुटियों के सुधार के माध्यम से उद्योग समझौता ज्ञापनों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करना सुनिश्चित करेगा।

* मौजूदा औद्योगिक और आर्थिक गलियारों का विस्तार:

राज्य के हर कोने में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए बंगाल के मौजूदा ६ औद्योगिक और आर्थिक गलियारों (रघुनाथपुर-ताजपुर, दानकुनी-कल्याणी, दानकुनी-झारग्राम, दानकुनी-कोचबिहार, खड़गपुर-मोर्ग्राम, पुरुलिया के गुरुडी से कोलकाता के जोका तक) का विस्तार किया जाएगा।

* जंगल सुंदरी वर्क सिटी परियोजना का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन:

पुरुलिया के रघुनाथपुर में एक अभूतपूर्व ग्रीनफील्ड औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए जंगलसुंदरी कर्मनगरी परियोजना पर काम में तेजी लाई जाएगी। इस पहल से राज्य में ७ लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

* ६५ लाख कारीगरों को सहयोग देने के लिए दो नए रत्न एवं आभूषण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे:

सोने, तांबे और चांदी के आभूषणों, विशेष रूप से महीन तार के काम से बने आभूषणों के निर्माण में बंगाल अग्रणी राज्य है, जो मुख्य रूप से बंगाल में ही पाए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय कारीगरों को विश्व स्तरीय आभूषण व्यापारियों से जोड़ने के लिए, हावड़ा और हुगली में दो विशेष रत्न एवं आभूषण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।





११. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

मुख्य उद्देश्य

- अगले ५ वर्षों में ६० लाख नए उद्यमों का सृजन करके और एमएसएमई की संख्या को ९० लाख से बढ़ाकर १५ करोड़ करके, बंगाल एमएसएमई इकाइयों की संख्या के मामले में नंबर १ राज्य के रूप में स्थापित होगा।

- ३०० नए एमएसएमई क्लस्टर और ४ क्षेत्रीय एमएसएमई निर्यात हब की स्थापना करके उद्यमिता और निर्यात को और मजबूत किया जाएगा, जिससे राज्य भर में ५ लाख नए उद्यमियों का उदय संभव होगा।

हमारी सफलता:

» पश्चिम बंगाल में ९० लाख से अधिक सक्रिय लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। सक्रिय एमएसएमई की संख्या के मामले में हम भारत में दूसरे स्थान पर हैं और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई में पहले स्थान पर हैं।

» एमएसएमई क्लस्टरों में १४ गुना वृद्धि हुई है, जो २०११ में ४९ क्लस्टरों से बढ़कर फरवरी २०२६ तक ७१० से अधिक हो गए हैं।

» सरकारी स्वामित्व वाले एमएसएमई औद्योगिक पार्कों की संख्या २०११ में २९ पार्कों से बढ़कर २०२६ में ५४ हो गई है, जिसमें एकीकृत वस्त्र पार्क, निर्दिष्ट रेशम पार्क और कृषि-औद्योगिक पार्क आदि शामिल हैं।

» हमारी सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से किए गए हस्तक्षेप के कारण, एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण प्रवाह २०११ में १२,३०० करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर २०२५ तक २ लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो १६ गुना वृद्धि है।

» २०११ से पहले, एक भी सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक पार्क नहीं था; आज ऐसे ४७ पार्क हैं।

» भारत का सबसे बड़ा चमड़ा पार्क पश्चिम बंगाल के बंतला में स्थित है, जो ५ लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

» स्वयं सहायता समूहों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार ने ५४० विपणन परिसर/हाट स्थापित किए हैं; जिनमें बोलपुर में बिस्वा माइक्रो मार्केट, अलीपुर में चमड़ा और कुटीर उत्पाद विपणन केंद्र - शिल्पन्ना, न्यूटाउन में बंग्लार हाट और राज्य के भीतर और बाहर बिस्वा बांग्ला और बंग्लार साड़ी ब्रांडों के साथ कुल ३६ दुकानें शामिल हैं।

» पिछले ११ वर्षों में, राज्य में बुनकरों को लगभग १,१७,००० करघे वितरित किए गए हैं।

» सरकारी सहायता से १,५०० से अधिक आधुनिक पावरलूम स्थापित किए गए हैं, जिससे कपड़े का वार्षिक उत्पादन बढ़कर १०० मिलियन मीटर हो गया है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* MSME इकाइयों के मामले में बंगाल को नंबर १ राज्य बनाना:
  पश्चिम बंगाल वर्तमान में ९० लाख से अधिक MSME इकाइयों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगले ५ वर्षों में ६० लाख नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिससे यह संख्या १.५ करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो देश में सबसे अधिक होगी।

* लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों (एमएसएमई) के क्लस्टरों और उद्यमिता का विस्तार:
  राज्य भर में ३०० नए एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करके, अगले ५ वर्षों में बंगाल से ५ लाख उद्यमी सृजित किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए १५ लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।

* १५० नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना:
  आर्थिक विकास को गति देने और नए उद्योगपतियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में १५० नए पूरी तरह से सुसज्जित औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

* निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय MSME निर्यात केंद्रों की स्थापना:
  हावड़ा, दुर्गापुर, बरहमपुर और सिलीगुड़ी में चार क्षेत्रीय MSME निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग और हस्तशिल्प जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

* प्राकृतिक रेशों के पुनरुद्धार का मिशन:
  जूट उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक मिशन चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य लुप्त हो रही जूट मिलों को पुनर्जीवित करना और जूट उत्पादों को अधिक विपणन योग्य और लोकप्रिय बनाना है। इसके साथ ही, अन्य प्राकृतिक रेशों और वस्त्रों के पुनरुद्धार और प्रचार पर भी अधिक जोर दिया जाएगा।

* राज्य की अनूठी हस्तशिल्पों को 'मेड इन बंगाल' की मान्यता:
  मेड इन बंगाल' पुरस्कार का शुभारंभ राज्य की अनूठी और विशिष्ट हस्तकलाओं को बढ़ावा देने, मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। यह पहल उत्पादों की विशिष्टता और वास्तविक पहचान सुनिश्चित करेगी और प्राचीन शिल्पकलाओं को संरक्षित करेगी।इससे स्थानीय कारीगरों की आजीविका भी मजबूत होगी। इसमें तुलैपंजी चावल, बिष्णुपुरी चंदन, टेराकोटा की मूर्तियाँ, डोकरा कला जैसे पारंपरिक उत्पाद शामिल होंगे; साथ ही सर्वेक्षण के माध्यम से शामिल किए जाने वाले कई नए उत्पाद भी शामिल होंगे।

* बिस्वा बांग्ला की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और उपस्थिति को और मजबूत करना: विश्व बांग्ला को एक प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा, जो बंगाल की बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों और रचनात्मक उद्योगों की सर्वोत्तम कृतियों को विश्व के सामने प्रस्तुत करेगा। इस पहल में शामिल होंगे:

  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
  - -जीआई टैग वाले उत्पादों का व्यापक प्रचार
  - ई-कॉमर्स के दायरे को और अधिक विस्तारित करना
  - -उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन की सख्त प्रणाली
  - अंतरराष्ट्रीय खुदरा विपणन कंपनियों के साथ साझेदारी
  - -समकालीन डिजाइनों का नवाचार और व्यापक ब्रांडिंग प्रचार।इन सभी का उद्देश्य बिस्वा बांग्ला को वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और सांस्कृतिक गौरव के अटूट प्रतीक के रूप में स्थापित करना है।





१२. स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्य उद्देश्य

- प्रत्येक ब्लॉक और शहर में वार्षिक 'द्वारे चिकित्सा' कैंप आयोजित करने और सभी ब्लॉक-स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में उचित मूल्य की दवाओं की दुकानें स्थापित करके, सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी।

- स्वास्थ्य साथी अस्पताल नेटवर्क का विस्तार करके और आधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ प्रत्येक जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधा सुनिश्चित करके, उन्नत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और क्षमता को और अधिक मजबूत किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ:

» २०११ से बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च ६ गुना बढ़ गया है।

» स्वास्थ्य साथी योजना के तहत २.४५ करोड़ परिवारों के ८.७२ करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला है। राज्य के लगभग ८५% परिवार इस योजना के दायरे में शामिल हैं।

» स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग ७०,००० करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, १४ नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, ४२ सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, १३,५०० से अधिक स्वास्थ्य केंद्र, ७६ सीसीयू (CCU), ३ एचडीयू (HDU), १७ मातृ एवं शिशु केंद्र, १३ मातृ प्रतीक्षा झोपड़ियाँ, ११७ उचित मूल्य की दवा दुकानें और १५८ मुफ्त निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

» हमारे राज्य में सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या २०११ में ७१,२०० से बढ़कर ९७,००० हो गई है, जो ३६.२५% की वृद्धि है।

» बंगाल की टेलीमेडिसिन पहल, स्वास्थ्य इंगित (Health Indications) के तहत ७ करोड़ से अधिक परामर्श सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या १,३५५ से बढ़कर ६,३४९ हो गई है।

» एमबीबीएस सीटों की संख्या १,३५५ से बढ़कर ६,३४९ हो गई है।

» स्वास्थ्य बंधु परियोजना के तहत लोगों के घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए २१० मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं।

» शिशु साथी परियोजना के तहत, ६४,००० बच्चों को जीवन रक्षक हृदय शल्य चिकित्सा से लाभ हुआ है।

» आई लाइट प्रोजेक्ट के तहत २६ लाख लोगों को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी और ३४ लाख लोगों को मुफ्त चश्मे मिले हैं।

» नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की कुल संख्या २,२६५ से बढ़कर २८,५४७ हो गई है।

» २०२५ में, बंगाल में संस्थागत प्रसव की दर ९९.१३% तक पहुँच गई; मातृ मृत्यु दर घटकर १०४ और शिशु मृत्यु दर घटकर १७ प्रति १,००० हो गई।

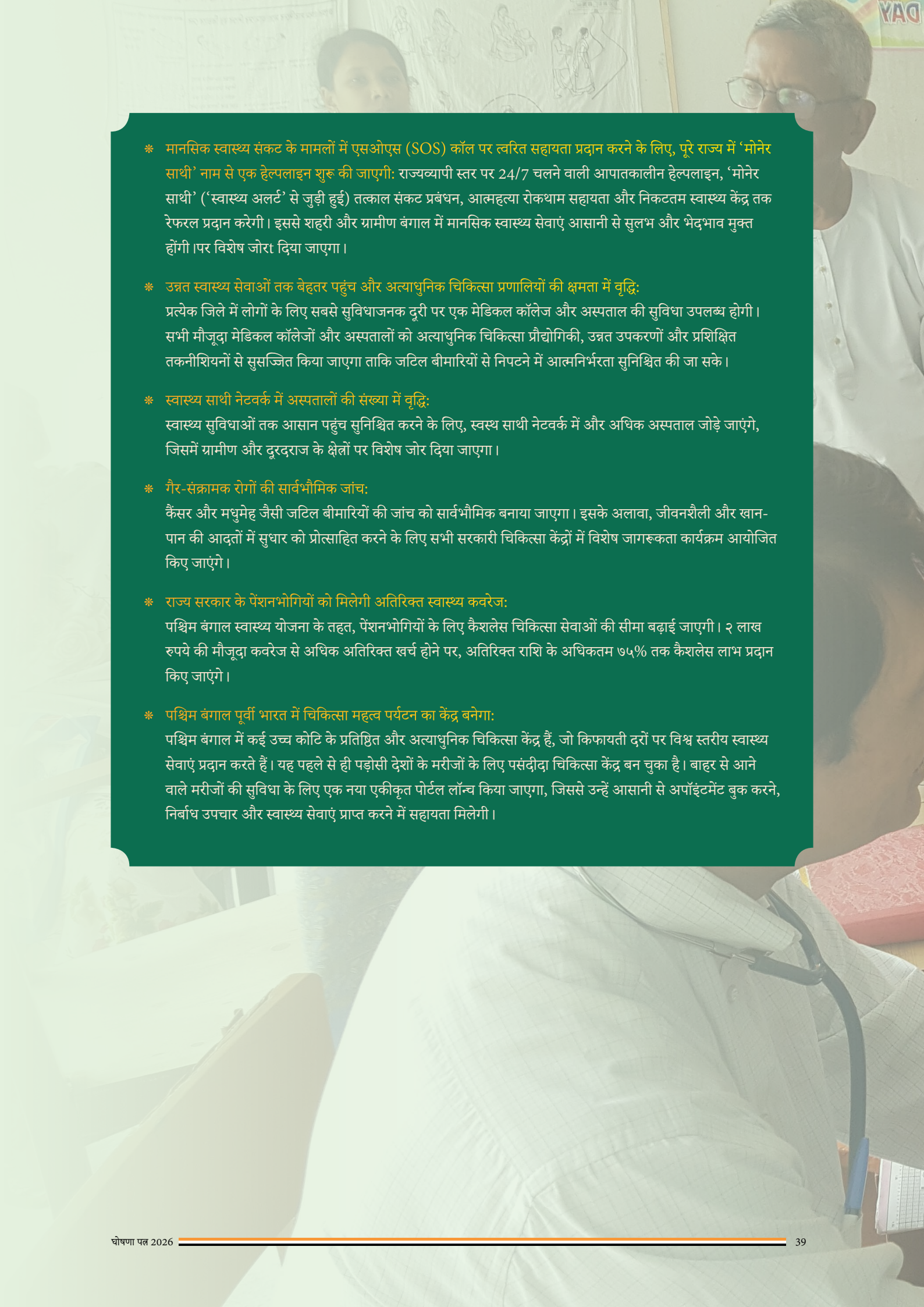
» पश्चिम बंगाल सरकार की पहल के तहत, कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित कॉर्ड ब्लड बैंक (स्टेम सेल संरक्षण केंद्र) स्थापित किया गया है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* हर ब्लॉक और शहर में साल में एक बार घर-घर जाकर द्वारे चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे:
  उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, व्यक्तिगत रेफरल, दवाएं और एक विशिष्ट रोगी ट्रैकिंग और सहायता प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि आगे के उपचार तक पहुंच हो, ताकि कोई भी मरीज उपचार से वंचित न रहे।

* प्रत्येक ब्लॉक में उचित मूल्य की दवा दुकानें:
  सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों में ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य की दवा दुकानें स्थापित की जाएंगी ताकि आम दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जा सकें और नागरिकों पर लागत का बोझ कम हो सके।

* राज्य में समर्पित किडनी बैंकों की स्थापना:
  बंगाल में अंग प्रत्यारोपण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए, राज्य भर में समर्पित किडनी बैंक स्थापित किए जाएंगे, ताकि सही समय पर उचित और नैतिक तरीके से किडनी का संरक्षण, वितरण और प्रत्यारोपण करना आसान हो सके।



- मानसिक स्वास्थ्य संकट के मामलों में एसओएस (SOS) कॉल पर त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए, पूरे राज्य में 'मोनेर साथी' नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी: राज्यव्यापी स्तर पर 24/7 चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन, 'मोनेर साथी' ('स्वास्थ्य अलर्ट' से जुड़ी हुई) तत्काल संकट प्रबंधन, आत्महत्या रोकथाम सहायता और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक रेफरल प्रदान करेगी। इससे शहरी और ग्रामीण बंगाल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से सुलभ और भेदभाव मुक्त होंगी।पर विशेष जोरt दिया जाएगा।

- उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि:
  प्रत्येक जिले में लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक दूरी पर एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी मौजूदा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उन्नत उपकरणों और प्रशिक्षित तकनीशियनों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि जटिल बीमारियों से निपटने में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके।

- स्वास्थ्य साथी नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या में वृद्धि:
  स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, स्वस्थ साथी नेटवर्क में और अधिक अस्पताल जोड़े जाएंगे, जिसमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

- गैर-संक्रामक रोगों की सार्वभौमिक जांच:
  कैंसर और मधुमेह जैसी जटिल बीमारियों की जांच को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। इसके अलावा, जीवनशैली और खान-पान की आदतों में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सरकारी चिकित्सा केंद्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

- राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को मिलेगी अतिरिक्त स्वास्थ्य कवरेज:
  पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना के तहत, पेंशनभोगियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाओं की सीमा बढ़ाई जाएगी। २ लाख रुपये की मौजूदा कवरेज से अधिक अतिरिक्त खर्च होने पर, अतिरिक्त राशि के अधिकतम ७५% तक कैशलेस लाभ प्रदान किए जाएंगे।

- पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में चिकित्सा महत्व पर्यटन का केंद्र बनेगा:
  पश्चिम बंगाल में कई उच्च कोटि के प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो किफायती दरों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यह पहले से ही पड़ोसी देशों के मरीजों के लिए पसंदीदा चिकित्सा केंद्र बन चुका है। बाहर से आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए एक नया एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उन्हें आसानी से अपॉइंटमेंट बुक करने, निर्बाध उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।





१३. शिक्षा

मुख्य उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आधुनिक शिक्षण अवसंरचना की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने के लिए, राज्य भर में कुल ४३० मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल होगा।

- बांग्लार शिक्षायातन के तहत, सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और उन्नत बुनियादी ढांचे सहित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ:

» सरकार की प्रमुख और पुरस्कार विजेता योजना 'कन्याश्री' के माध्यम से १ करोड़ लड़कियों की मदद की गई है।

» सबुज साथी योजना के तहत १.४४ करोड़ से अधिक छात्रों को साइकिलें मिली हैं।

» लगभग १.६५ करोड़ छात्रों (प्राथमिक से कक्षा १२ तक) को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

» हर साल, विभिन्न कक्षाओं के १.०६ करोड़ छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते और स्कूल बैग प्रदान किए जाते हैं।

» मध्याह्न भोजन योजना (प्राथमिक से कक्षा आठवीं तक) के तहत नामांकित १.१ करोड़ छात्रों को नियमित रूप से गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

» सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन दर के मामले में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर है, जो ८९% है; जबकि इस संबंध में राष्ट्रीय औसत ५२% है।

» २०२३ से बंगाल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में ड्रॉपआउट दर शून्य हो जाएगी।

» छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने में सहायता देने के लिए, 'तरुणेर स्वप्नो' योजना के तहत ५३ लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।

» छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से १ लाख से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा के अपने सपनों को साकार करने का लाभ मिला है।

» स्वामी विवेकानंद योग्यता-सह-साधन योजना के तहत ३३.६५ लाख छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है।

» क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ४५६ संताली माध्यम के विद्यालय, १९८ राजबंशी माध्यम के विद्यालय और २ कामतापुरी माध्यम के विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

» २०११ में बंगाल में १२ विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में, बंगाल में विश्वविद्यालयों की संख्या ४२ है और राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या १२ से बढ़कर ३१ हो गई है।

» बंगाल के दो राज्य विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष २० विश्वविद्यालयों में शामिल हैं।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एआई प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि छात्रों को प्रौद्योगिकी-आधारित कार्य जगत के लिए तैयार किया जा सके:
  यह सुनिश्चित करना कि बंगाली छात्र अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस युग में रोजगार बाजार के लिए तैयार हों।

* सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बंगाल के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना:
  बंगाल के बच्चे हमारे राज्य की विरासत और विविधता के बारे में अच्छी तरह से सूचित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो बंगाल के पुनर्जागरण के गौरवशाली काल सहित राज्य के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करेगा।

* राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की स्थापना:
  एशियाई विकास बैंक (ADB) की लगभग २,५०० करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से राज्य में कुल ४३० मॉडल स्कूल

बनाए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक और ८७ पिछड़े ब्लॉकों में दो-दो मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे।

* शिक्षा पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के ४.५% तक बढ़ाना:
  यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य शिक्षा अवसंरचना का विस्तार कर सके और सभी स्तरों पर शिक्षकों को पर्याप्त सहायता प्रदान कर सके, सरकार शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के ४.५% तक बढ़ाएगी।

* बंगाल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का समग्र अवसंरचनात्मक विकास:
  जिन विद्यालयों को तत्काल विकास की आवश्यकता है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास प्रदान किया जाएगा। इस विकास में नौ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: बहते पानी वाले शौचालय, पर्याप्त शिक्षक, विद्युतीकरण, फर्नीचर, रंगाई, सामान्य मरम्मत, हरित ब्लैकबोर्ड, स्मार्ट कक्षाएँ, कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ और चारदीवारी।

* सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में रोजगार संबंधी कौशल प्रशिक्षण:
  शिक्षा से रोजगार तक के मार्ग को सुगम बनाने के लिए, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में एक कौशल विकास केंद्र होगा, जहां छात्रों को साक्षात्कार प्रशिक्षण, भाषा कौशल और सॉफ्ट स्किल्स विकास के अवसर मिलेंगे।





१४. खाद्य

मुख्य उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए और सब्सिडी वाले खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर, प्रत्येक पात्र परिवार को 'खाद्य साथी' योजना के दायरे में लाकर समावेशी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- अपव्यय को रोकने के लिए, अनाज की खरीद से लेकर वितरण तक पारदर्शी और त्वरित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्न परिवहन में 'एंड-टू-एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम' लागू करना।

हमारी उपलब्धियाँ:

» खाद्य साथी योजना के तहत, बंगाल में लगभग ९ करोड़ लोगों को १,०९,४६८ करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण रियायती राशन प्राप्त हुआ है।

» दुआरे राशन योजना के तहत, ७.५ करोड़ लाभार्थियों को १,७१७ करोड़ रुपये की लागत से उनके घर पर राशन वितरण का लाभ मिला है।

» बायोमेट्रिक्स आधारित स्व-सेवा सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की जटिलताओं को दूर करते हुए त्वरित सेवा वितरण संभव हो गया है।

» खाद्यान्न भंडारण क्षमता २०११ में ६३,००० मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान में लगभग १.२५ मिलियन मीट्रिक टन हो गई है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* अनाज परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक वाहन की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना:
धान संग्रहण केंद्रों से राइस मिल, वहाँ से वितरक और अंततः राशन डीलर की दहलीज तक, प्रत्येक चरण में वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए 'रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग' शुरू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार के अपव्यय या अनियमितता को पूरी तरह से रोकना है।

* सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और जिम्मेदार सेवा सुनिश्चित करना:
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में प्रत्येक पात्र परिवार खाद्य साथी योजना के अंतर्गत आए और कोई भी पीछे न छूटे। वस्तुओं का हस्तांतरण आसान और निर्बाध होगा। स्व-सेवाओं को सरल बनाया जाएगा और असहाय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को सहायता निरंतर प्रदान की जाती रहेगी।





१५. सड़कें

मुख्य लक्ष्य:

- राज्य भर में संपर्क व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु आगामी ५ वर्षों में पथश्री परियोजना के अंतर्गत १५,००० किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- उन्नत सड़क अभियांत्रिकी, नियमों का कड़ाई से अनुपालन तथा त्वरित आपातकालीन सेवाओं जैसे ठोस एवं साक्ष्य-आधारित उपायों को अपनाकर सड़क सुरक्षा में सुधार किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियां:

» वर्ष २०११ से राज्य भर में कुल १,८३,०८४ किलोमीटर राज्य सड़कों, ग्रामीण सड़कों तथा अन्य सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में ३६१ बड़े एवं मध्यम पुल तथा २० आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कुल व्यय लगभग ८३,००० करोड़ रुपये हुआ है।

» पथश्री १, २ एवं ३ परियोजनाओं के अंतर्गत, केंद्र की पीएमजीएसवाई (PMGSY) निधि बंद रहने के बावजूद पूरे राज्य में संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु १०,९०२ करोड़ रुपये के व्यय से ३९,००० किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। पथश्री ४ परियोजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने ८,४८८ करोड़ रुपये के व्यय से २०,०३० किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य आरंभ किया है।

» सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग के माध्यम से बंगाल इस क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन का अग्रदूत बनकर उभरा है। इसके अंतर्गत ३,६३९ ग्रामों में ६,५०० किलोमीटर से अधिक प्लास्टिक सड़कों के निर्माण की योजना है।

» पश्चिम बंगाल के दक्षिण २४ परगना में हाथानिया-दोआनिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए उत्कृष्ट कार्य की मान्यता स्वरूप हमारे राज्य को नेशनल हाईवे एक्सीलेंस गोल्ड अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।

» माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने २,५०० करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ४४.२ किलोमीटर लंबी कल्याणी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। १६ किलोमीटर लंबी बेलघरिया एक्सप्रेसवे से जुड़ा यह सिग्नल-मुक्त ४–६ लेन का कॉरिडोर २१ फ्लाईओवर, एलिवेटेड स्ट्रेचेज तथा ६-लेन अंडरपास से सुसज्जित है। इस परियोजना ने कल्याणी से हवाई अड्डे तक यात्रा समय को घटाकर ४० मिनट कर दिया है, कापा मोड़ होते हुए बेलघरिया से बड़ो जागुलिया तक मार्ग को पूर्णतः सिग्नल-मुक्त बनाया है, तथा इसके साथ ही उत्तर २४ परगना और नदिया जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास को और सुदृढ़ किया है।

आगामी वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* पथाश्री योजना के अंतर्गत अगले ५ वर्षों में १५,००० किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण: राज्य के सभी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रभावी सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, 'पथाश्री' योजना के अंतर्गत अगले ५ वर्षों में १५,००० किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, २,५५,४८५ किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का नियमित उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा।

* सड़क सुरक्षा के लिए विशेष उपाय:
रोकथाम योग्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु उन्नत सड़क अभियांत्रिकी, कानूनों का कड़ाई से अनुपालन, जनजागरूकता तथा त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सहित ठोस एवं साक्ष्य-आधारित उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।





१६. जल

मुख्य उद्देश्य

- राज्य के सभी १.७५ करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करते हुए 'जलस्वप्न' योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे प्रत्येक घर तक नल के जल का १००% उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके।

- सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जल प्रदूषण का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी और इनकी संख्या २१६ से बढ़ाकर ३६५ की जाएगी।

हमारी उपलब्धियाँ

» ग्रामीण बंगाल में 'जलस्वप्न' योजना के माध्यम से १ करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल के जल का कनेक्शन पहुंचाया गया है। वहीं, १५ वर्ष पहले यह संख्या केवल २.१४ लाख ही थी।

» २,८४७ नल आधारित जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने और उन्हें चालू किए जाने के माध्यम से पश्चिम बंगाल के ६.५० करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

» बंगाल में २१६ जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित है, जिनमें से सभी एनएबीएल (NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हैं, जो देश में सबसे अधिक है।

» 'जलस्वप्न' योजना के कार्यान्वयन हेतु 'महात्मा-श्री' के अंतर्गत कुल २१.६८ लाख जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुल १३.९० करोड़ कार्यदिवस सृजित हुए हैं और मजदूरी के रूप में कुल ३,५७० करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

» 'जल धरो जल भरो' कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल भर में ५ लाख जलाशयों, जल संचयन संरचनाओं तथा वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे सिंचाई, भूजल स्तर और ग्रामीण जल सुरक्षा को मजबूती मिली है।

» लंबे समय तक केंद्र द्वारा लंबित रखे जाने के बावजूद, FMBAP के अंतर्गत प्रस्तुत 'घाटाल मास्टर प्लान' की पूरी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। राज्य सरकार पहले ही ११५ किलोमीटर नदी की खुदाई (ड्रेजिंग) के लिए ३४१ करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और अब कुल १,५०० करोड़ रुपये की लागत से अगले दो वर्षों में इस परियोजना को अपने स्तर पर पूर्ण करेगी।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का संकल्प लेते हैं:

* सभी के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, घरों में १००% कार्यात्मक नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे:
  'जलस्वप्न' मिशन के तहत और ७५ लाख परिवारों को कार्यात्मक नल से जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य के सभी १.७५ करोड़ ग्रामीण परिवारों तक यह सुविधा पहुंच जाएगी।

* प्रत्येक ब्लॉक में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी:
  प्रत्येक ब्लॉक में प्रयोगशाला की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जल परीक्षण केंद्रों की संख्या २१६ से बढ़ाकर ३६५ की जाएगी। इससे पानी में किसी भी प्रकार के प्रदूषण का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा और जलजनित रोगों की रोकथाम संभव होगी।



१७. बिजली

मुख्य उद्देश्य

- ५,००० मेगावाट थर्मल पावर विस्तार, ७५० मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और १,००० मेगावाट तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना सहित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाकर,चरम मांग अवधि के दौरान बिजली कटौती को शून्य तक लाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और परिवारों, किसानों तथा विभिन्न उद्यमों या व्यवसायों के लिए 'सुनिश्चित पावर क्रेडिट' के साथ राज्यव्यापी सोलर ग्रिड शुरू करके, पर्यावरण के अनुकूल बिजली वितरण प्रणाली को तेज़ किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ:

» बिजली क्षेत्र में ९०,००० करोड़ रुपये के निवेश के परिणामस्वरूप, बंगाल अब १००% विद्युतीकरण के माध्यम से बिजली अधिशेष वाला राज्य बन गया है।

» जबकि २०११ में ३८१ ब्लॉक कम वोल्टेज की समस्या से ग्रस्त थे, २०२२ में यह संख्या घटकर शून्य हो गई है।

» भारत की दूसरी सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड ने पिछले १५ वर्षों में १७५% की वृद्धि हासिल की
है - १५.५ करोड़ नए ग्राहक जोड़े हैं और अब इसके कुल ग्राहक २४.५ करोड़ हैं।

» सागरदिघी, संतालदिही और बक्रेश्वर स्थित ताप विद्युत संयंत्र लगातार भारत के शीर्ष दस विद्युत संयंत्रों में शुमार रहे हैं।

» पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली ६६० मेगावाट की सुपरक्रिटिकल यूनिट सागरदिघी में ४,५६७ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की गई है, जो १६.७ लाख घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इससे २६,००० प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। बिजली उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए, शालबनी में १६,००० करोड़ रुपये के निवेश से १,६०० मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है, जिससे १५,००० प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

» पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (WBSETCL) ने बिजली पारेषण में होने वाले नुकसान को घटाकर २.१४% कर दिया है और निर्बाध बिजली उपलब्धता को ९९.९६% तक बढ़ा दिया है, जो भारत की सभी बिजली पारेषण कंपनियों में सबसे अच्छा है।

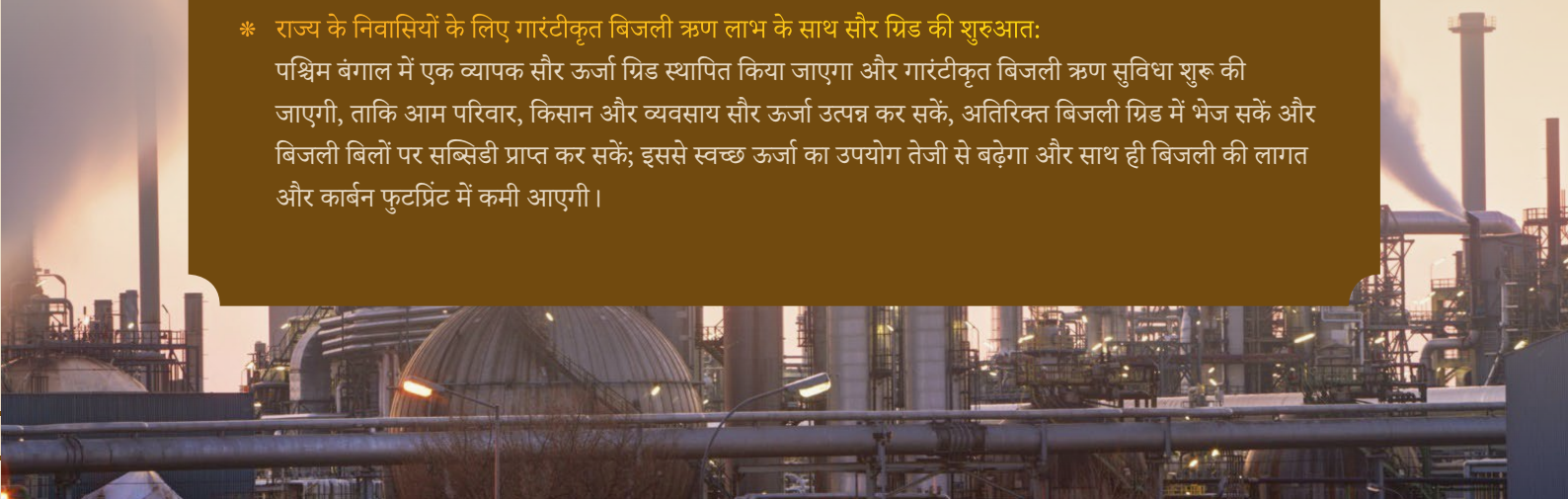
» पहली बार, डब्ल्यूबीपीडीसीएल (WBPDCL) के बिजली संयंत्रों की कोयले की पूरी आवश्यकता स्वयं की खदानों से पूरी की गई है, जिससे कोल इंडिया की सहायक कंपनियों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। उसी वर्ष, डब्ल्यूबीपीडीसीएल ने राज्य सरकार को १०४ करोड़ रुपये का लाभांश दिया और सागरदिघी में ४०.९६ करोड़ रुपये के निवेश से ५ मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* अधिकतम मांग के दौरान भी बिजली कटौती नहीं होगी:
राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें तापीय ऊर्जा उत्पादन को ५,००० मेगावाट तक बढ़ाना, ७५० मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और १,००० मेगावाट की तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करना शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकतम मांग वाले महीनों में भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो।

* हरित ऊर्जा पर अधिक ध्यान:
ग्रीन हाइड्रोजन नीति की अधिसूचना और नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते खर्च के साथ, पश्चिम बंगाल अब जलवायु के प्रति जागरूक भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

* राज्य के निवासियों के लिए गारंटीकृत बिजली ऋण लाभ के साथ सौर ग्रिड की शुरुआत:
पश्चिम बंगाल में एक व्यापक सौर ऊर्जा ग्रिड स्थापित किया जाएगा और गारंटीकृत बिजली ऋण सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि आम परिवार, किसान और व्यवसाय सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकें, अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेज सकें और बिजली बिलों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकें; इससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ेगा और साथ ही बिजली की लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी।





१८. पर्यटन

मुख्य उद्देश्य

- बंगाल को भारत का नंबर १ पर्यटन स्थल बनाना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का विस्तार करके विदेशी पर्यटकों की संख्या को प्रतिवर्ष ५ करोड़ तक बढ़ाना।

- बंगाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए शिव-शक्ति, वैष्णव और बौद्ध सर्किट सहित एकीकृत धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे।

हमारी सफलता:

» पश्चिम बंगाल में MICE (बैठकें, प्रोत्साहन कार्यक्रम, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ) क्षेत्र में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। हमारे राज्य ने वित्त वर्ष २०२४-२५ में १,१८५ और वित्त वर्ष २०२५-२६ में १,३०० ऐसे आयोजनों की मेजबानी की है।

» बंगाल में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के लिए बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर, बिस्वा बांग्ला मेला परिसर और धान्य धान्य सभागार जैसे शीर्ष स्थानों का एक नेटवर्क, साथ ही १५० से अधिक स्टार श्रेणी के होटल उपलब्ध कराए गए हैं।

» बंगाल में ४४ आलीशान होटलों के निर्माण के लिए ६,५१० करोड़ रुपये के भारी निवेश का वादा किया गया है, जिससे १०,००० रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

» राज्य के पर्यटन विभाग ने ६ सांस्कृतिक क्षेत्रों में ४०० से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों सहित १०० से अधिक धार्मिक पर्यटन परिपथों की पहचान कर उन्हें उन्नत बनाया है।

» भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए 'इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम २०२५' के अनुसार, विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में पश्चिम बंगाल देश में दूसरे स्थान पर है। अक्टूबर २०२५ तक बंगाल ने २४.२४ करोड़ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया है।

» कोलकाता को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, न्यूटाउन में एक इको पार्क (प्रकृति तीर्थ) बनाया गया है - जो ४८० एकड़ में फैली हरियाली के बीच स्थित ११२ एकड़ का एक विशाल और शानदार जलाशय है। इसके अलावा, रवींद्र तीर्थ, नजरुल तीर्थ, मदर वैक्स म्यूजियम और कोलकाता गेट जैसे कई पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के स्थल बनाए गए हैं। बैरकपुर में वीर शहीद मंगल पांडे की स्मृति में 'उत्सधारा' पर्यटन परियोजना शुरू की गई है।

» चाय पर्यटन के विकास ने स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित किए हैं, जिससे उन्हें अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल रही है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आर्थिक विकास और अधिक तेज़ हो रहा है।

आने वाले वर्षों में हम निम्नलिखित कार्य करने का वादा करते हैं:

* बंगाल को पर्यटन में नंबर १ राज्य बनाना:

  पश्चिम बंगाल ने २०२४ तक घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में देश में दूसरा स्थान पहले ही हासिल कर लिया है। हम प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध अपने राज्य को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित करेंगे। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर साल कम से कम ५ करोड़ विदेशी पर्यटक बंगाल आएं।

* भारत में बैठकों, प्रोत्साहन कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) पर्यटन में पश्चिम बंगाल को अग्रणी बनाने के लिए:

  राज्य भर में फैले कन्वेंशन हॉल, सभागारों और आयोजन स्थलों के बढ़ते नेटवर्क का लाभ उठाकर बंगाल को भारत के अगले प्रमुख एमआईसीई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

❋ पश्चिम बंगाल में तीन अलग-अलग एकीकृत धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे: शिव-शक्ति सर्किट, वैष्णव सर्किट और बौद्ध सर्किट:

पश्चिम बंगाल में तीन एकीकृत धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। इनमें कोलकाता-बीरभूम-हुगली तक फैला शिव-शक्ति सर्किट, नादिया-हुगली-मुर्शिदाबाद-मेदिनपुर तक फैला वैष्णव सर्किट और उत्तरी बंगाल तथा पश्चिमी पठार क्षेत्र को जोड़ने वाला बौद्ध सर्किट शामिल हैं। इन सर्किटों के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर संचार व्यवस्था, स्वच्छ बुनियादी ढांचा, सुरक्षित आवास और आधुनिक सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

❋ बिष्णुपुर और बीरभूम के लिए दो नए पर्यटन पैकेज:

राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए, दो नए विशेष पर्यटन पैकेज शुरू किए जाएंगे। इनमें से एक पैकेज बीरभूम जिले में शांतिनिकेतन को केंद्र में रखकर पेश किया जाएगा, और दूसरा पैकेज बिष्णुपुर के मंदिर-नगर को केंद्र में रखकर पेश किया जाएगा।




DARJEELING
HIMALAYAN RAILWAY
DHR
924



१९. संस्कृति

मुख्य उद्देश्य

- बंगाल की भाषाई विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु राजबंशी एवं कुर्माली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे।

- बंगाल की समृद्ध फिल्म परंपरा के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण के उद्देश्य से प्रख्यात फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक को समर्पित एक अत्याधुनिक फिल्म अभिलेखागार एवं फिल्म पुनर्स्थापन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ

» लोकप्रसार योजना के अंतर्गत १.९२ लाख लोक कलाकारों को सहायता प्रदान की जा रही है (रिटेनर कलाकार: १.५ लाख, पेंशनभोगी: ४२,०००), जिन्हें प्रति माह ₹१,००० की रिटेनर राशि/पेंशन प्रदान की जाती है।

» बंगाल का दुर्गा पूजा, जो प्रतिवर्ष लगभग ७०,००० करोड़ रूपये की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage of Humanity) के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।

» २५० करोड़ रूपये की लागत से निर्मित दीघा स्थित जगन्नाथ धाम राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रमुख प्रतीक है। इसके साथ ही, गंगासागर सेतु, माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर एवं सांस्कृतिक परिसर तथा न्यू टाउन में दुर्गा अंगन जैसी परियोजनाएँ राज्य के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को सुदृढ़ कर रही हैं।

» संथाली, कुड़ुख, कुर्माली, राजबंशी, कामतापुरी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, ओड़िया, नेपाली एवं पंजाबी भाषाओं को सरकारी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो भाषाई विविधता एवं समावेशन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

» वर्ष २०२३ में सारना/सारी धर्म की मान्यता हेतु विधानसभा में विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

» नवद्वीप एवं कूचबिहार को हेरिटेज शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा तारकेश्वर, तारापीठ, बक्रेश्वर एवं पाथरचापुरी के लिए विकास बोर्ड गठित किए गए हैं।

» दक्षिणेश्वर (रानी रासमणि स्काईवॉक), कालीघाट स्काईवॉक एवं जलेश मंदिर स्काईवॉक का निर्माण किया गया है।

» राज्यभर में अनेक मंदिरों का संरक्षण, पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।

» बाबा लोकनाथ धाम, श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र आश्रम एवं माँ सारदा देवी के निवास का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही, ओंकारनाथ सरणी का नामकरण एवं स्मारक द्वार का निर्माण किया गया है।

» स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास एवं सिस्टर निवेदिता से संबंधित भवनों का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है तथा 'विवेकतीर्थ' के रूप में एक शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया जा रहा है।

» फुरफुरा शरीफ एवं गाजी जाफर खान दरगाह का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया गया है।

» आदिवासी सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया गया है तथा संबंधित स्थलों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

» बाबुरहाट में महाबीर चिला राय की १५ फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो क्षेत्रीय इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करती है।

आगामी वर्षों के लिए हमारी प्रतिबद्धताएँ

* आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का प्रयास:

  राजबंशी एवं कुर्माली भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु केंद्र सरकार के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखे जाएंगे, ताकि इन भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समुचित सम्मान एवं मान्यता प्राप्त हो सके।

* ठाकुर पंचानन वर्मा के पैतृक घर, मंदिर और तीर्थस्थल का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण:

  पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों को आधिकारिक तौर पर "राज्य मेले" का दर्जा दिया

जाएगा। इनमें उत्तर 24 परगना का बरुणी मेला, बीरभूम का केंडुली मेला और अलीपुरद्वार का महाकाल शिवरात्रि उत्सव शामिल हैं।, बांकुरा में बिष्णुपुर मेला, बीरभूम में बकरेश्वर मेला, हुगली में तारकेश्वर सरबोनी मेला, हावड़ा में रामोत्सव मेला, जलपाईगुड़ी में जलपेश सरबोनी मेला, नादिया में बारोडोल मेला, मिदनापुर में उर्स मेला, मुर्शिदाबाद में खोड़ा खिजिर उत्सव, दक्षिण 24 परगना में बनबीबी उत्सव और कूच बिहार में रास उत्सव।इस दर्जे से इन मेलों को बेहतर बुनियादी ढांचा, सुरक्षा उपाय और प्रचार-प्रसार में सरकारी सहायता मिलेगी। इससे न केवल सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा, बल्कि मेलों के आसपास के क्षेत्रों में कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा।

* ऋत्विक घटक फिल्म अभिलेखागार एवं पुनर्स्थापन केंद्र:

ऋत्विक घटक के सम्मान में एक अत्याधुनिक फिल्म अभिलेखागार एवं पुनर्स्थापन केंद्र स्थापित किया जाएगा।इस केंद्र में फिल्मों के मूल रील, पटकथाएँ, पोस्टर एवं अन्य अभिलेख संरक्षित किए जाएंगे।आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फिल्मों का पुनर्स्थापन एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा।यह केंद्र फिल्म निर्माताओं, विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं के लिए एक उन्नत अभिलेख एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

* सभी भारतीय भाषाओं में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत भाषा के रूप में बंगाली भाषा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना:

बंगाली भाषा को तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाने हेतु विशेष पहल की जाएगी।युवाओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स एवं संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि:

  * उन्नत डिजिटल उपकरणों एवं अनुप्रयोगों का विकास हो सके
  * वॉयस रिकग्निशन एवं टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीकों का निर्माण किया जा सके
  * उच्च गुणवत्ता वाले बहुभाषीय अनुवाद मॉडल विकसित किए जा सकें
  * डिजिटल अभिलेखागार एवं ओपन-सोर्स भाषा संसाधनों का निर्माण किया जा सके

* बारुईपुर में कल्चरल सिटी का विकास: बारुईपुर में 'टेली अकादमी' के आधार पर एक आधुनिक कल्चरल सिटी विकसित की जाएगी।इससे राज्य के टेलीविजन एवं सांस्कृतिक उद्योग को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाएगा।

❋ राज्य मेला का दर्जा एवं समर्थन:

पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों को आधिकारिक तौर पर "राज्य मेले" का दर्जा दिया जाएगा। इनमें उत्तर 24 परगना का बरुणी मेला, बीरभूम का केंडुली मेला और अलीपुरद्वार का महाकाल शिवरात्रि उत्सव शामिल हैं।, बांकुरा में बिष्णुपुर मेला, बीरभूम में बकरेश्वर मेला, हुगली में तारकेश्वर सरबोनी मेला, हावड़ा में रामोत्सव मेला, जलपाईगुड़ी में जलपेश सरबोनी मेला, नादिया में बारोडोल मेला, मिदनापुर में उर्स मेला, मुर्शिदाबाद में खोड़ा खिजिर उत्सव, दक्षिण 24 परगना में बनबीबी उत्सव और कूच बिहार में रास उत्सव।इस दर्जे से इन मेलों को बेहतर बुनियादी ढांचा, सुरक्षा उपाय और प्रचार-प्रसार में सरकारी सहायता मिलेगी। इससे न केवल सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा, बल्कि मेलों के आसपास के क्षेत्रों में कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा।





२०. स्पोर्ट्स

मुख्य उद्देश्य

- दैनिक खेलकूद में भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में कम्युनिटी टर्फ, मल्टी-स्पोर्ट एरेना तथा स्थानीय खेल मैदानों के उन्नयन सहित आधुनिक क्रीड़ा अवसंरचना का विकास किया जाएगा।

- डुमुरजला में अत्याधुनिक सुविधाओं तथा एक समेकित स्पोर्ट्स मेडिसिन हब के साथ एक स्पोर्ट्स सिटी स्थापित की जाएगी, जो उच्चस्तरीय खिलाड़ियों के विकास में बंगाल की क्षमता को और सुदृढ़ करेगी।

हमारी उपलब्धियाँ

» खेलाश्री परियोजना के अंतर्गत ३८,४२५ क्लबों को प्रथम वर्ष में ₹२ लाख तथा अगले तीन वर्षों में प्रति वर्ष ₹१ लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ऑफ एथलेटिक्स (BOA) में पंजीकृत ३४ राज्य स्तरीय संघों को ₹५ लाख प्रति संघ तथा १,३२१ कोचिंग कैंपों को ₹१ लाख प्रति कैंप की सहायता प्रदान की गई है।

» साथ ही, वर्ष २०२३ से १,५८० सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को ₹१,००० प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है।

» राज्यभर में फुटबॉल, तैराकी, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस तथा टेबल टेनिस के लिए ८ स्पोर्ट्स अकादमियाँ स्थापित की गई हैं।

» राज्य में ७४ स्टेडियम एवं ४४ युवा छात्रावास स्थापित किए गए हैं तथा उनका नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया गया है।

» प्रख्यात पर्वतारोहियों को सम्मानित करने हेतु तेनजिंग नोर्गे–राधानाथ सिकदर पुरस्कार तथा छंदा गाएन वीरता पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं।

» राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता से संचालित क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

» ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मडन एससी तथा मोहुन बागान एफसी के अवसंरचनात्मक विकास हेतु २७ करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है तथा उन्हें बंगविभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है।

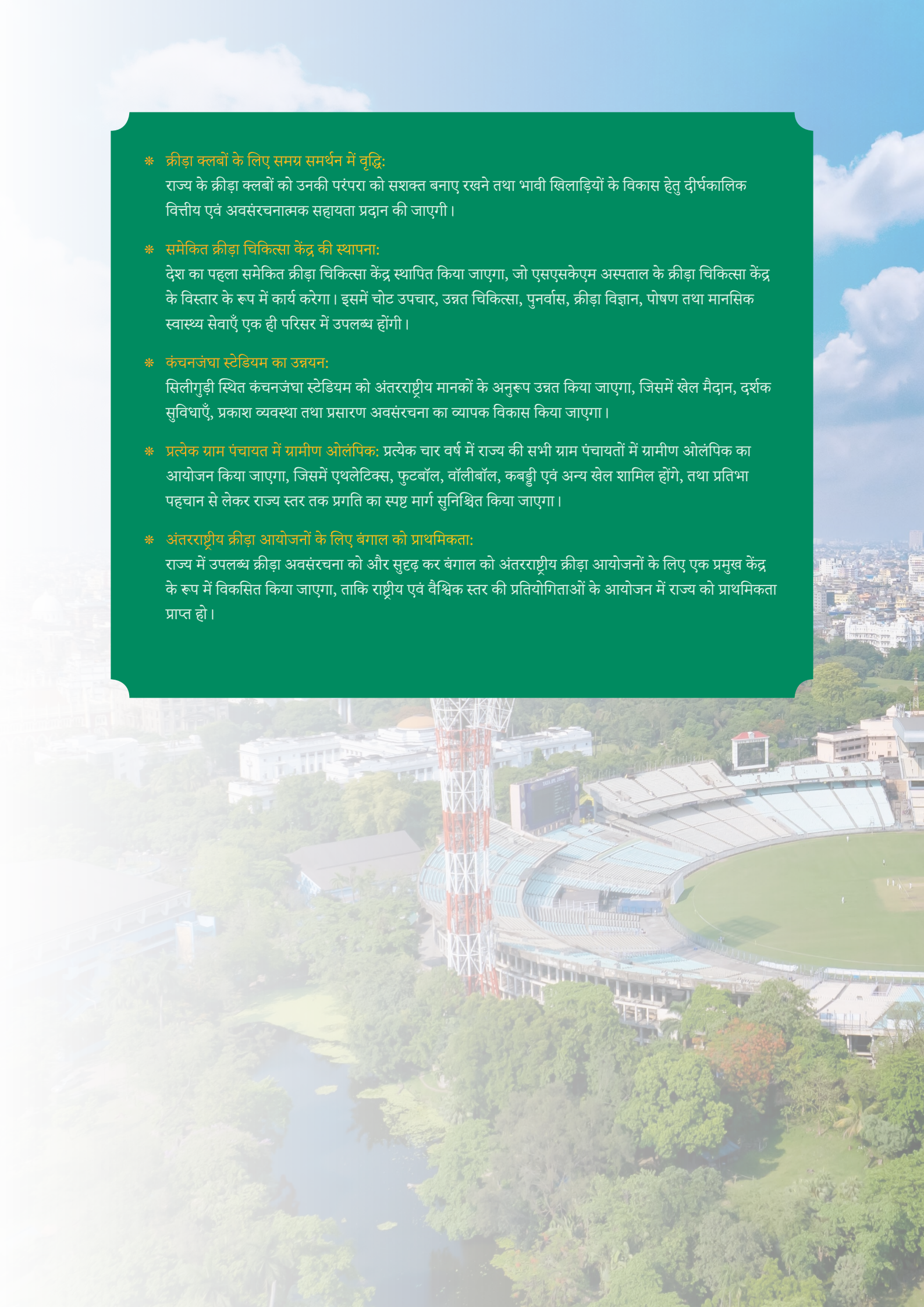
आगामी वर्षों के लिए हमारी प्रतिबद्धताएँ

* शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में क्रीड़ा अवसंरचना का विकास:
  राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने हेतु शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में क्रीड़ा अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत सुलभ दरों पर उपयोग योग्य कम्युनिटी टर्फ, छोटे मल्टी-स्पोर्ट एरेना तथा स्थानीय खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे दैनिक खेलकूद एवं प्रशिक्षण हेतु सुरक्षित, पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त तथा सुलभ स्थान सुनिश्चित किए जा सकें।

* राज्यव्यापी वार्षिक क्रीड़ा प्रतिभा खोज कार्यक्रम:
  युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से संभावनाशील खिलाड़ियों की पहचान कर उनकी प्रतिभा का विकास किया जाएगा तथा युवाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

* नई क्रीड़ा अकादमियों की स्थापना:
  जिम्नास्टिक्स, योग, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स तथा अन्य उभरते खेलों के लिए नई क्रीड़ा अकादमियाँ स्थापित की जाएँगी, जिससे प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण तथा विश्वस्तरीय कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

* डुमुरजला में क्रीड़ा नगर की स्थापना:
  डुमुरजला में एक आधुनिक क्रीड़ा नगर विकसित किया जाएगा, जिसमें उन्नत अवसंरचना एवं समेकित क्रीड़ा चिकित्सा केंद्र उपलब्ध होगा।



- **क्रीड़ा क्लबों के लिए समग्र समर्थन में वृद्धि:**
  राज्य के क्रीड़ा क्लबों को उनकी परंपरा को सशक्त बनाए रखने तथा भावी खिलाड़ियों के विकास हेतु दीर्घकालिक वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।

- **समेकित क्रीड़ा चिकित्सा केंद्र की स्थापना:**
  देश का पहला समेकित क्रीड़ा चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो एसएसकेएम अस्पताल के क्रीड़ा चिकित्सा केंद्र के विस्तार के रूप में कार्य करेगा। इसमें चोट उपचार, उन्नत चिकित्सा, पुनर्वास, क्रीड़ा विज्ञान, पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

- **कंचनजंघा स्टेडियम का उन्नयन:**
  सिलीगुड़ी स्थित कंचनजंघा स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा, जिसमें खेल मैदान, दर्शक सुविधाएँ, प्रकाश व्यवस्था तथा प्रसारण अवसंरचना का व्यापक विकास किया जाएगा।

- **प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण ओलंपिक:** प्रत्येक चार वर्ष में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एवं अन्य खेल शामिल होंगे, तथा प्रतिभा पहचान से लेकर राज्य स्तर तक प्रगति का स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।

- **अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजनों के लिए बंगाल को प्राथमिकता:**
  राज्य में उपलब्ध क्रीड़ा अवसंरचना को और सुदृढ़ कर बंगाल को अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजनों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन में राज्य को प्राथमिकता प्राप्त हो।





२१. पर्यावरण

मुख्य उद्देश्य

- गंगा नदी के कटाव को रोकने तथा प्रभावित जनसमुदाय के जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदा एवं मुर्शिदाबाद जिलों हेतु एक व्यापक रिवरबैंक प्रोटेक्शन मास्टर प्लान लागू किया जाएगा।

- बंगाल के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन एवं एक जैव-विविधता जीन बैंक की स्थापना के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण को और सुदृढ़ किया जाएगा।

हमारी उपलब्धियाँ

» पिछले १५ वर्षों में पश्चिम बंगाल का वन क्षेत्र २,६८८ वर्ग किलोमीटर (१८.९१%) बढ़कर १४,२१४ वर्ग किलोमीटर से १६,९०२ वर्ग किलोमीटर हो गया है।

» राज्य योजना (स्टेट प्लान) के अंतर्गत १.४ लाख हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया गया है।

» दक्षिण २४ परगना एवं पूर्व मेदिनीपुर के तटीय क्षेत्रों में १५ करोड़ से अधिक मैंग्रोव पौधों का रोपण किया गया है।

» 'जल धरो जल भरो' कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल भर में ५ लाख जलाशयों, जल संरक्षण संरचनाओं तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया है।

आगामी वर्षों के लिए हमारी प्रतिबद्धताएँ

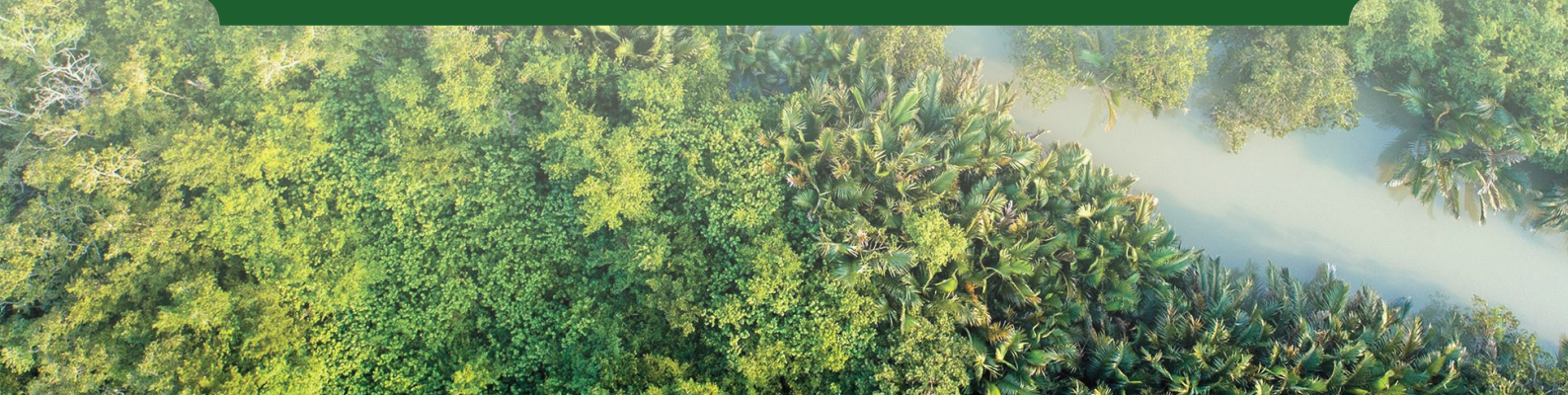
* मालदा एवं मुर्शिदाबाद के लिए नदी तट संरक्षण मास्टर प्लान: गंगा नदी के तटों के निरंतर कटाव को रोकने तथा मुर्शिदाबाद एवं मालदा के निवासियों के जीवन, आजीविका एवं आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र एवं दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नदी प्रबंधन विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया जाएगा।इस योजना में उन्नत हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, वैज्ञानिक नदी प्रबंधन उपाय, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, जियो-टेक्सटाइल आधारित सुदृढ़ीकरण, आवश्यकता अनुसार स्थायी ड्रेजिंग तथा पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के माध्यम से संवेदनशील एवं क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, योजना में अग्रिम चेतावनी प्रणाली, समुदाय पुनर्वास हेतु अवसंरचना तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सक्षम रणनीतियाँ सम्मिलित होंगी, जिससे अस्थायी राहत के स्थान पर स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके तथा कृषि भूमि, महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं नदी तटीय समुदायों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

* आर्द्रभूमि पुनर्वास: पूर्व एवं पश्चिम कोलकाता की आर्द्रभूमियाँ एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक हॉटस्पॉट का निर्माण करती हैं। इन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सरकार व्यापक सर्वेक्षण कराएगी, फीडर जलधाराओं का पुनरुद्धार करेगी तथा बिना उपचारित अपशिष्ट के निस्तारण को पूर्णतः प्रतिबंधित करेगी।

* जैव-विविधता जीन बैंक की स्थापना: पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकारी वित्तीय सहयोग से एक जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जो लुप्तप्राय वनस्पति एवं जीव प्रजातियों के जैविक अभिलेखों के संरक्षण हेतु कार्य करेगा।यह जीन बैंक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण विशेषज्ञों के परामर्श से स्थापित किया जाएगा तथा तीव्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के बीच बंगाल की जैव-विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से कार्य करेगा।

* मैंग्रोव संरक्षण केंद्र की स्थापना: एक केंद्रीकृत मैंग्रोव संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो २४×७ निगरानी एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित करेगा।यह केंद्र साप्ताहिक उपग्रह-आधारित परिवर्तनों की निगरानी करेगा तथा चक्रवात एवं ज्वार-भाटा जनित तटबंध क्षति के संबंध में अग्रिम चेतावनी प्रदान करेगा।
साथ ही, वनकर्मियों की तैनाती एवं जमीनी स्तर की गतिविधियों के संचालन हेतु रीयल-टाइम (तत्काल) डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा।

* औद्योगिक क्षेत्रों हेतु कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण नीति: पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण नीति लागू की जाएगी।



धन्यवाद

पिछले १५ वर्षों से हमने बंगाल की जनता से किए गए हर वादे को निभाया है। हमारा घोषणापत्र केवल चुनावी आकर्षण नहीं है, बल्कि जनता के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर एक अभूतपूर्व बदलाव लाया है और इससे हमें यह विश्वास मिलता है कि आने वाला मार्ग और भी सुंदर तथा उदाहरणीय होगा।

भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए हमारा लक्ष्य स्पष्ट है; करुणा, ईमानदारी और साहस के साथ कार्य करना। बंगाल की गरिमा, विविधता और शांति को बनाए रखते हुए प्रत्येक घर तक प्रगति पहुंचाना ही हमारा संकल्प है। साथ ही, हम समाज को संकीर्ण विभाजनों में बांटने वाली राजनीति का दृढ़तापूर्वक विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल सदैव से सद्भाव के आदर्शों में विश्वास करता आया है। इसलिए, भय और विभाजन की राजनीति के माध्यम से हमारे राज्य की संस्कृति, पहचान और सामाजिक एकता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे।

यह घोषणापत्र एक नई प्रतिबद्धता है, जनता की बात सुनने, उस पर कार्य करने और बंगाल की सद्भावपूर्ण संस्कृति की रक्षा करने की। इसके साथ ही, हम एक सशक्त, न्यायपूर्ण और भविष्य के लिए तैयार राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

बंगाल की शांति, एकता और प्रगति के हित में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना मत दें।

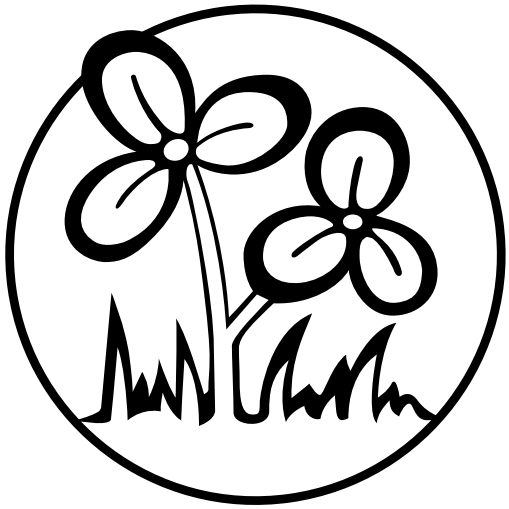
आपका अटूट विश्वास और एकजुट होकर आगे बढ़ने की भावना ही हमारा मार्गदर्शन करती है। आगामी १८वें विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहें और राज्य भर में हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करें। उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ, हम आपको बंगाली नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं और नमस्कार देते हैं।

जय हिंद! जय बंगाल! जय मां-माटी-मानुष!

प्रस्तुतकर्ता

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस





अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

बंगाल की विरासत और गौरव की रक्षा करें
टीएमसी के प्रतीक पर अपना वोट दें

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष, सुब्रत बक्षी द्वारा
प्रकाशित मुद्रणः एडीओ प्रिंट, कोलकाता - 700135 , Qty.: 25

